नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 235
दि. 29.05.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

त्विषा शर्मा मौत मामले में बड़ा मोड़: पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह गिरफ्तार, सीबीआई की कार्रवाई से भोपाल में मचा हड़कंप

भोपाल। राजधानी भोपाल के चर्चित और संवेदनशील त्विषा शर्मा मौत मामले में गुरुवार को उस समय बड़ा मोड़ आ गया, जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया। करीब सात घंटे तक चली लंबी पूछताछ, मेडिकल रिपोर्ट और बयानों में मिले विरोधाभासों के बाद की गई इस कार्रवाई ने पूरे मामले को नई दिशा दे दी है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक इस घटनाक्रम की चर्चा तेज हो गई है और कानूनी तथा प्रशासनिक हलकों में भी हलचल मच गई है।

सीबीआई की विशेष टीम गुरुवार सुबह नई दिल्ली से भोपाल पहुंची थी। टीम में महिला अधिकारी भी शामिल थीं। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी सीधे बागमुगालिया स्थित गिरिबाला सिंह के निवास पर पहुंची, जहां पहले से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया था। बागसेवनिया, मिसरोद और कटारा हिल्स थाना पुलिस के साथ विशेष सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी। घर के बाहर बैरिकेडिंग कर आम लोगों और मीडिया की आवाजाही सीमित कर दी गई थी।

यह कार्रवाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के एक दिन बाद हुई। अदालत के फैसले के बाद माना जा रहा था कि सीबीआई जल्द ही उनसे सख्ती से पूछताछ कर सकती है। गुरुवार सुबह शुरू हुई पूछताछ देर शाम तक चली। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी ने इस दौरान कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे और घटनाक्रम से जुड़े तकनीकी तथा परिस्थितिजन्य सबूतों को सामने रखकर जवाब मांगे।

पूछताछ के दौरान सीबीआई ने गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को आमने-सामने बैठाकर भी सवाल किए। समर्थ सिंह पहले से सीबीआई रिमांड पर हैं और उन्हें

29 मई को अदालत में पेश किया जाना है। जांच एजेंसी का कहना है कि दोनों के बयानों में गंभीर विरोधाभास पाए गए हैं। इन्हीं विसंगतियों ने संदेह को और गहरा कर दिया। मामले की संवेदनशीलता इसलिए भी अधिक है क्योंकि त्विषा शर्मा की शादी महज पांच महीने पहले ही हुई थी। 9 दिसंबर 2025 को उनकी शादी समर्थ सिंह से हुई थी और 12 मई 2026 को भोपाल स्थित ससुराल में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शुरुआत में इसे सामान्य घटना बताने की कोशिश हुई, लेकिन परिवार की शिकायतों, परिस्थितियों और बाद में सामने आए तथ्यों ने मामले को गंभीर बना दिया। लगातार बढ़ते दबाव और सवालों के बाद जांच सीबीआई को सौंपी गई थी।

जांच एजेंसी के सूत्रों के अनुसार एम्स भोपाल की मेडिकल रिपोर्ट ने मामले को पूरी तरह बदल दिया। रिपोर्ट में त्विषा शर्मा के शरीर पर मौत से पहले चोटों के निशान मिलने की पुष्टि हुई है। सीबीआई अब इन चोटों को कथित प्रताड़ना और संदिग्ध परिस्थितियों से जोड़कर देख रही है। अधिकारियों का मानना है कि मेडिकल रिपोर्ट और घटनास्थल से मिले अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह मामला केवल सामान्य मृत्यु का नहीं माना जा सकता।

गिरफ्तारी के बाद देर शाम गिरिबाला सिंह को मेडिकल जांच के लिए भोपाल एम्स ले जाया गया। अस्पताल परिसर में भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। सीबीआई अधिकारी लगातार कानूनी प्रक्रिया पूरी करने में जुटे रहे। माना जा रहा है कि मेडिकल औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्हें विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया जाएगा, जहां जांच एजेंसी आगे की पूछताछ के लिए रिमांड की मांग कर सकती है। पूरे मामले ने राज्य के न्यायिक और प्रशासनिक तंत्र को भी झकझोर दिया है। एक पूर्व जिला जज की गिरफ्तारी को बेहद असाधारण घटनाक्रम माना जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि किसी न्यायिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के खिलाफ इतनी गंभीर कार्रवाई की जाती है, तो इसका मतलब है कि जांच एजेंसी को पर्याप्त प्राथमिक साक्ष्य मिले हैं। हालांकि अंतिम निर्णय अदालत में पेश किए जाने वाले सबूतों और सुनवाई पर निर्भर करेगा।

त्विषा शर्मा के परिवार ने शुरुआत से ही मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की थी। परिवार का आरोप रहा है कि उनकी बेटी को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था। अब मेडिकल रिपोर्ट में चोटों के निशान मिलने के बाद परिवार के आरोपों को और गंभीरता से देखा जा रहा है। मामले ने सोशल मीडिया पर भी व्यापक चर्चा पैदा कर दी है और लोग लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं।

भोपाल में गुरुवार का पूरा दिन इसी घटनाक्रम के इर्द-गिर्द घूमता रहा। गिरिबाला सिंह के घर के बाहर मीडिया कर्मियों की भारी भीड़ लगी रही। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी थी कि आसपास रहने वाले लोग भी हैरान नजर आए। सीबीआई अधिकारियों ने पूरे ऑपरेशन को बेहद गोपनीय और नियंत्रित तरीके से अंजाम दिया।

राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। महिला संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं माना जाना चाहिए। वहीं कानूनी हलकों में यह बहस भी शुरू हो गई है कि क्या इस मामले में आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं।

सीबीआई सूत्रों का कहना है कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और कई अहम पहलुओं की जांच की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन सहित कई बिंदुओं को खंगाला जा रहा है। एजेंसी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना से पहले और बाद में क्या-क्या गतिविधियां हुईं और किसने क्या भूमिका निभाई। अब पूरे मामले पर सबकी नजर आगामी अदालत पेशी पर टिकी है। यह माना जा रहा है कि सीबीआई अदालत से लंबी रिमांड मांग सकती है ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। जांच एजेंसी को उम्मीद है कि पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के जरिए आने वाले दिनों में कई और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं।

त्विषा शर्मा मौत मामला अब केवल एक पारिवारिक त्रासदी नहीं रह गया है, बल्कि यह न्याय, प्रभाव और जवाबदेही से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है। गुरुवार को हुई गिरफ्तारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है और आने वाले दिन इस पूरे मामले में कई नए खुलासों के गवाह बन सकते हैं।

सीमा सुरक्षा पर बड़ा दांव: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 'चिकन नेक' की रणनीतिक जमीन BSF को सौंपी, बंगाल में सुरक्षा ढांचे को मिलेगी नई मजबूती

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से गुरुवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा को और मजबूत करने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लेते हुए रणनीतिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील माने जाने वाले 'चिकन नेक' इलाके की 121 हेक्टेयर जमीन सीमा सुरक्षा बल (BSF) को सौंप दी है। इसके साथ ही राज्य के नौ सीमावर्ती जिलों में कुल 142.79 एकड़ अतिरिक्त जमीन भी बीएसएफ को हस्तांतरित की गई है। राज्य सरकार के इस कदम को राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और पूर्वोत्तर भारत की रणनीतिक मजबूती के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।

सरकार के अनुसार इस जमीन का उपयोग नए बॉर्डर आउटपोस्ट, सीमा चौकियों, फेंसिंग और सुरक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा। लंबे समय से लंबित माने जा रहे इस फैसले को राज्य मंत्रिमंडल ने 11 मई को हुई पहली बैठक में मंजूरी दी थी। उसी बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 45 दिनों के भीतर लगभग 600 एकड़ जमीन बीएसएफ को सौंपी जाएगी। अब सरकार ने पहले चरण में

महत्वपूर्ण इलाकों की जमीन हस्तांतरित कर स्पष्ट संकेत दिया है कि सीमा सुरक्षा को लेकर वह तेजी से काम करना चाहती है।

इस फैसले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने राज्य सरकार की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत-बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा देश की आंतरिक और सामरिक मजबूती के लिए बेहद जरूरी है। शाह ने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान किए गए वादे के अनुरूप सरकार ने तेजी से कार्रवाई करते हुए केवल सात दिनों के भीतर चिकन नेक क्षेत्र की जमीन बीएसएफ को सौंप दी। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया।

'चिकन नेक' या सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के सबसे संवेदनशील भूभागों में गिना जाता है। यह संकरा भूभाग देश के पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के मुख्य भूभाग से जोड़ता है। रणनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार यदि इस क्षेत्र की सुरक्षा में किसी भी तरह की कमजोरी आती है, तो उसका सीधा असर पूरे पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है। यही वजह है कि वर्षों से इस इलाके को सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता रहा है।

विशेषज्ञ बताते हैं कि इस कॉरिडोर की चौड़ाई कई स्थानों पर बेहद कम है और इसके आसपास अंतरराष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं। एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ बांग्लादेश और पास में भूटान जैसे पड़ोसी देशों की भौगोलिक स्थिति इसे और अधिक संवेदनशील बनाती है। ऐसे में बीएसएफ की मौजूदगी और मजबूत सुरक्षा ढांचा इस क्षेत्र की सामरिक मजबूती के लिए अनिवार्य माना जाता है। राज्य सरकार ने जिन नौ जिलों में बीएसएफ को जमीन उपलब्ध कराई है, उनमें कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया और उत्तर 24 परगना शामिल हैं। ये सभी जिले भारत-बांग्लादेश सीमा से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से अवैध घुसपैठ, तस्करी तथा सीमा पार अपराधों को लेकर चर्चा में रहे हैं।

सरकारी सूत्रों के अनुसार इन इलाकों में नई सीमा चौकियां स्थापित की जाएंगी और अधूरी फेंसिंग के कार्य को तेजी से पूरा किया जाएगा। राज्य सरकार और बीएसएफ दोनों का मानना है कि बेहतर निगरानी व्यवस्था और मजबूत बुनियादी ढांचे से सीमा प्रबंधन अधिक प्रभावी हो सकेगा। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ लगभग 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। यह देश की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में से एक है। हालांकि इनमें से करीब 600 किलोमीटर हिस्से में अब भी पूरी तरह फेंसिंग नहीं हो पाई है। यही कारण है कि कई क्षेत्रों में अवैध घुसपैठ, पशु तस्करी, नकली मुद्रा, हथियारों की आवाजाही और अन्य आपराधिक गतिविधियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां लगातार चिंता जताती रही हैं। राज्य सरकार का कहना है कि नई जमीन उपलब्ध होने से बीएसएफ को सीमा सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी। खासतौर पर उन इलाकों में जहां अब तक भूमि संबंधी बाधाओं के कारण सुरक्षा ढांचे का विस्तार नहीं हो पा रहा था। राजनीतिक दृष्टि से भी यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक बहस का केंद्र रहा है। भाजपा लगातार राज्य में अवैध घुसपैठ और सीमा सुरक्षा को लेकर पूर्ववर्ती सरकारों पर सवाल उठाती रही है। अब सत्ता में आने के बाद सरकार इस मुद्दे पर तेजी से फैसले लेकर अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक प्राथमिकताएं स्पष्ट करना चाहती है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि केवल फेंसिंग या चौकियों की संख्या बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि आधुनिक तकनीक, निगरानी उपकरण, ड्रोन सर्विलांस और बेहतर सड़क नेटवर्क की भी आवश्यकता होगी। हालांकि जमीन हस्तांतरण को इस दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सरकारी अधिकारियों के मुताबिक इससे पहले भी कई चरणों में बीएसएफ को जमीन सौंपी जा चुकी है, लेकिन इस बार प्रक्रिया को और अधिक तेज किया गया है। सरकार अब उन लंबित परियोजनाओं को भी जल्द पूरा करना चाहती है, जो वर्षों से भूमि विवाद या प्रशासनिक मंजूरी के कारण अटकी हुई थीं। स्थानीय स्तर पर इस फैसले को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई लोग इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण और स्थानीय प्रभावों को लेकर चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि सभी प्रक्रियाएं नियमों के तहत पूरी की जा रही हैं और स्थानीय लोगों के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत-बांग्लादेश सीमा केवल सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह आर्थिक, सामाजिक और सामरिक दृष्टि से भी बेहद अहम है। ऐसे में यदि सीमा प्रबंधन मजबूत होता है, तो इसका असर केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सीमा क्षेत्रों के विकास और स्थिरता पर भी पड़ेगा।

"पहाड़ों से उठी रोशनी की कहानी": सिक्किम बना पूर्ण साक्षर राज्य, भारत के शिक्षा इतिहास में जुड़ा नया अध्याय

नई दिल्ली/गंगटोक। भारत के शिक्षा इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ गया है। हिमालय की गोद में बसा छोटा सा लेकिन प्रगतिशील राज्य सिक्किम अब देश का पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रपति Droupadi Murmu की उपस्थिति में गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित एक विशेष समारोह में यह ऐतिहासिक घोषणा की गई। इस उपलब्धि के साथ सिक्किम भारत का पांचवां पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है और पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह उपलब्धि हासिल करने वाला तीसरा राज्य है।

यह घोषणा केवल एक सरकारी उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक लंबे सामाजिक, शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयासों का परिणाम है, जिसने पहाड़ों और दुर्गम इलाकों में शिक्षा की अलख जगाई। केंद्र सरकार की ULLAS (Understanding of Lifelong Learning for All in Society) पहल के तहत यह लक्ष्य हासिल किया गया, जिसका उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाना और उन्हें जीवनभर सीखने के अवसर प्रदान करना है।

इस उपलब्धि के साथ सिक्किम उन चुनिंदा राज्यों की सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त किया है। इससे पहले मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। खास बात यह है कि पूर्वोत्तर भारत में यह तीसरा राज्य है जिसने पूर्ण साक्षरता हासिल कर देश को यह संदेश दिया है कि छोटे राज्य भी बड़े बदलाव की मिसाल बन सकते हैं।

कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने बताया कि सिक्किम में साक्षरता अभियान केवल पढ़ने-लिखने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास और सामाजिक जागरूकता को भी शामिल किया गया। गांव-गांव में चलाए गए अभियानों, स्वयंसेवी शिक्षकों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी ने इस लक्ष्य को संभव बनाया।

राज्य सरकार ने इस उपलब्धि को मुख्यमंत्री Prem Singh Tamang के नेतृत्व में चल रहे शैक्षिक सुधारों और सामाजिक समावेशन की नीतियों का परिणाम बताया है। सरकार का कहना है कि शिक्षा को केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि जीवन का आधार बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए गए, जिनका परिणाम आज सामने है। ULLAS योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य केवल पारंपरिक साक्षरता तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि लोगों को व्यावहारिक ज्ञान, डिजिटल दक्षता और जीवन कौशल से जोड़ना है। इस कार्यक्रम के तहत विशेष रूप से उन वयस्कों पर ध्यान दिया गया जो किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए थे।

"धरती तप रही है, आने वाले पांच साल और खतरनाक": यूएन चेतावनी के बीच भारत में भीषण लू और मौसम का असंतुलन बढ़ा

नई दिल्ली। पूरी दुनिया एक ऐसे जलवायु संकट की ओर बढ़ रही है, जिसका असर अब पहले से कहीं ज्यादा तीव्र और व्यापक दिखाई देने लगा है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की ताज़ा रिपोर्ट ने साफ चेतावनी दी है कि आने वाले पांच साल दुनिया के लिए और अधिक खतरनाक साबित हो सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2026 से 2030 के बीच वैश्विक तापमान के औद्योगिक युग से पहले की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस की सुरक्षित सीमा को पार करने की 75 प्रतिशत संभावना है। यह चेतावनी केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि आने वाले समय में मानव जीवन, कृषि, जल संसाधन और पर्यावरण पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों का संकेत है।

इसी वैश्विक चेतावनी के बीच भारत में मौसम का मिजाज तेजी से बिगड़ता नजर आ रहा है। उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस

मौसम का अब तक का सबसे अधिक स्तर है। हालात इतने गंभीर हैं कि सड़कों पर दोपहर के समय सन्नाटा छा जा रहा है और जरूरी काम के बिना लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं।

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने देश के कई हिस्सों में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। कई क्षेत्रों में तापमान सामान्य से कई डिग्री ऊपर दर्ज किया जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य जोखिम भी बढ़ गया है।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति केवल एक मौसमी बदलाव नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन का सीधा प्रभाव है, जो लगातार अधिक तीव्र होता जा रहा है। बढ़ते औद्योगिक उत्सर्जन, जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग और वनों की कटाई जैसे कारणों ने पृथ्वी के तापमान संतुलन को बिगाड़ दिया है। WMO की रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि कोयला, तेल और गैस के लगातार जलने से वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे लू, सूखा, बाढ़ और तूफानों जैसी घटनाएं अधिक बार और अधिक तीव्र रूप में सामने आ रही हैं।

मौसम विभाग ने किसानों के लिए भी विशेष सलाह जारी की है। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी की संभावना को देखते हुए फसलों की सुरक्षा के उपाय अपनाने को कहा गया है। पश्चिमी राजस्थान में भी तेज गर्मी के कारण कृषि कार्य प्रभावित हो सकता है। किसानों को मक्का, मूंग, दालें, गन्ना, सूरजमुखी और सब्जियों की फसलों की नियमित सिंचाई करने और मल्चिंग जैसे उपाय अपनाने की सलाह दी गई है ताकि मिट्टी की नमी बनी रहे।

इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम के तीव्र बदलाव की चेतावनी भी दी है। 29 मई को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और कुछ स्थानों पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक के झोंकों के साथ आंधी-तूफान आने की संभावना जताई गई है। कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिससे खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। विशेषज्ञों के अनुसार यह असामान्य मौसम पैटर्न जलवायु असंतुलन का संकेत है। एक ओर जहां भीषण गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर अचानक तेज आंधी, ओलावृष्टि और बारिश जैसे घटनाक्रम भी देखने को मिल रहे हैं। यह स्थिति कृषि, जल प्रबंधन और शहरी जीवन तीनों के लिए चुनौतीपूर्ण बनती जा रही है।

WMO की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यदि वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में चरम मौसम घटनाओं की तीव्रता और आवृत्ति दोनों बढ़ जाएंगी। इसका सबसे ज्यादा असर उन देशों पर पड़ेगा जहां जनसंख्या घनी है और संसाधनों पर पहले से दबाव है, जैसे भारत।

भारत में पिछले कुछ वर्षों में हीटवेव से होने वाली मौतों के आंकड़े भी चिंताजनक हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार वर्ष 2024 में लू लगने से 1,832 लोगों की मौत दर्ज की गई, जो पिछले दो दशकों में सबसे अधिक आंकड़ों में से एक है। इससे पहले 2015 में भीषण गर्मी के कारण 1,908 लोगों की जान गई थी।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि लू से बचाव के लिए सबसे जरूरी है समय पर सावधानी। दोपहर के समय बाहर निकलने से बचना, पर्याप्त पानी पीना, हल्के कपड़े पहनना और शरीर को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों के लिए यह स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है।

मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले सप्ताह में तापमान में अस्थायी गिरावट के बाद फिर से वृद्धि देखने को मिल सकती है। 31 मई से 2 जून के बीच उत्तर भारत में तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना जताई गई है, जिससे एक बार फिर लू का प्रभाव तेज हो सकता है।

संपादकीय

प्राथमिकता से प्रणालीगत सुधार करे सीबीएसई

अभी नीट प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पत्रों के लीक होने और परीक्षा रद्द होने की सुर्खियों की स्याही सूखी भी न थी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की मूल्यांकन प्रणाली सवालों के घेरे में आ गई। निश्चय ही ये घटनाक्रम छात्रों और प्रतियोगियों के परीक्षा व्यवस्था पर भरोसे को कम ही कर रहे हैं। आपदा में अवसर की तलाश में रहने वाले राजनीतिक दलों को छोड़ भी दें, तो भी आम लोग भी सीबीएसई की मूल्यांकन पद्धति पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल, सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम प्रणाली में खामियों और विसंगतियों को लेकर शिकायतें सामने आ रही हैं। कक्षा बारह के कुछ छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत अपलोड की गई स्कैन प्रतियों और उनकी उत्तर पुस्तिकाओं में विसंगति सामने आने का खुलासा किया है। निश्चित रूप से यह प्रकरण महज एक तकनीकी समस्या से कहीं अधिक का मामला है। यह भारत की उस शीर्ष परीक्षा प्रणाली की बढ़ती विफलता की चेतावनी है, जो लाखों छात्रों के भविष्य का निर्धारण करती है। इस घटनाक्रम में एक छात्र वेदांत श्रीवास्तव का मामला विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि सीबीएसई ने स्वयं स्वीकार किया है कि गलत उत्तर पुस्तिका भेजी गई थी। हालांकि, मामला तूल पकड़ता देख उसे बाद में सही उत्तर पुस्तिका भेज दी गई। इसी तरह एक अन्य परीक्षार्थी, संजना को भी सीबीएसई की तरफ से कमोबेश ऐसी ही प्रतिक्रिया मिली है। भला हो सोशल मीडिया का जो इन मुद्दों को देश की जनता के सामने तुरंत ले आता है और देश में इससे एक जनमत बनाने का अवसर मिलता है। हालांकि, यह स्वागत योग्य है कि सीबीएसई ने इन प्रणालीगत त्रुटियों को स्वीकार तो किया। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इस लापरवाही के लिये जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अन्यथा लापरवाही व गलती का यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। सीबीएसई को अपनी साख बचाये रखने के लिये इस दिशा में समय रहते सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यहां सवाल उठता है कि सीबीएसई जैसी परीक्षा नियामक संस्था ने अपने स्तर पर खामियों को दूर करने के लिये कारगर तंत्र क्यों विकसित नहीं किया। वह तब ही जागती है जब मीडिया में घटना सुर्खियां बनती है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि सीबीएसई ने तब कार्रवाई की और सुधारात्मक कदम उठाये, जब प्रभावित छात्रों ने इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान चलाया। निश्चित रूप से एक निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली में इतना लचीलापन होना चाहिए कि छात्रों के आक्रोश के सार्वजनिक होने, राजनीतिक टीका-टिप्पणी सामने आने या ऑनलाइन अभियान चलने से पहले समस्या का निराकरण हो जाए। हालिया घटनाक्रम का एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह भी है कि सीबीएसई की लापरवाही का शिकार बने वेदांत को अपनी बात उठाने पर बुरी तरह लांछित किया। कुछ सोशल मीडिया वीरों ने उसकी मुखरता से आवाज उठाने की कोशिश को देश विरोधी तक ही नहीं कहा, बल्कि कुछ ने तो उसे पाकिस्तानी तक कह दिया। यह तंत्र के बचाव में उतरने की अंधभक्ति ही है कि न्याय के लिये आवाज उठाने के लिये पीड़ित भारतीय नागरिक की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने की असफल कोशिश हो। क्या न्याय के लिये आवाज उठाने वाले छात्रों को इसलिए अपमानित व प्रताड़ित होना चाहिए क्योंकि उसकी शिकायत सामने आने के बाद देश के नामचीन संगठनों को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है? वास्तव में इन छात्रों के मामले में आई खामियों की व्यापक स्तर पर पड़ताल होनी चाहिए। यह भी विचार करना चाहिए कि कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण के बिना आनन-फानन में डिजिटलीकरण कराने से ही कहीं ऐसी खामियां तो सामने नहीं आ रही हैं? निश्चित रूप से इसका खमियाजा छात्रों को ही भुगतना पड़ता है और उनका भविष्य दांव पर लग जाता है। यह हकीकत है कि सीबीएसई का भूल सुधार करने का प्रयास कभी व्यवस्थागत सुधार का विकल्प नहीं हो सकता। बोर्ड को तत्काल ओएसएम प्रणाली और स्कैनिंग प्रक्रियाओं का स्वतंत्र ऑडिट कराना चाहिए। परीक्षा बोर्ड और परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियां योग्यता और निष्पक्षता की संरक्षक मानी जाती हैं। सवालों से घिरी भारतीय शिक्षा प्रणाली तभी अपनी विश्वसनीयता बचा सकती है, जब वह बुनियादी प्रक्रियात्मक विश्वसनीयता की गारंटी देने का वायदा करे।

सरकारी स्कूलों की आपराधिक उपेक्षा क्यों

> नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश के एक लाख 19 हजार सरकारी स्कूलों में बिजली नहीं है; 98,592 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है; चौदह हजार से अधिक स्कूलों में पीने का पानी नहीं है; एक लाख से अधिक स्कूलों में सिर्फ एक अध्यापक एक से अधिक कक्षाओं को पढ़ा रहा है।

स्कूली शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में 'नीति' आयोग ने एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। यह विडंबना ही है कि 'नीट' की परीक्षा में हुई धांधली की धूल में नीति-आयोग की यह रिपोर्ट कहीं खो सी गयी है। इस रिपोर्ट के कुछ आंकड़े सिर्फ चौंकाते ही नहीं, परेशान भी करते हैं। जैसे, यह रिपोर्ट बताती है कि देश में सरकारी और निजी स्कूलों की स्थितियों का अंतर शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की उपेक्षा को ही उजागर नहीं करता, बल्कि यह भी बता रहा है कि देश के भविष्य को लेकर हमारी चिंताएं कितनी खोखली हैं। प्रधानमंत्री एक से अधिक अवसरों पर अपने भाषणों में इस आशय के दावे कर चुके हैं कि देश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास कर रहा है। मसलन, एक भाषण में उन्होंने कहा था कि देश में प्रति सप्ताह एक नया विश्वविद्यालय खुल रहा है, हर रोज एक नया कॉलेज खुल रहा है। प्रधानमंत्री आईआईटी और आईआईएम के विस्तार के दावे भी कर चुके हैं। लेकिन नीति-आयोग की यह रिपोर्ट शिक्षा क्षेत्र की बुनियादी कमजोरियों को उजागर कर रही है। पिछले एक दशक के विश्लेषण पर आधारित यह रिपोर्ट बता रही है कि हमने शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को सरकारी और गैर-सरकारी में बांटकर समूची शिक्षा प्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिये हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश के एक लाख 19 हजार सरकारी स्कूलों में बिजली नहीं है; 98,592 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है; चौदह हजार से अधिक स्कूलों में पीने का पानी नहीं है; एक लाख से अधिक स्कूलों में सिर्फ एक अध्यापक एक से अधिक कक्षाओं को पढ़ा रहा है। रिपोर्ट में ऐसे और भी कई आंकड़े हैं जो यह बताते हैं कि शिक्षा जैसे बुनियादी क्षेत्र में

हम किस तरह की आपराधिक उपेक्षा बरत रहे हैं। उदाहरण के लिए सन् 2017 और 2024 के बीच देश में 87000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद हो गये, इसकी तुलना में निजी स्कूलों की जैसे बाढ़-सी आ रही है।

यह सही है कि हाल के कुछ सालों में, विशेष कर कोरोना-काल के बाद सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वालों की संख्या कुछ बढ़ी है, पर इसका कारण शिक्षा का स्तर नहीं, अभिभावकों की आर्थिक विवशता कहीं अधिक है।

वैसे, यह भी एक विडंबना ही है कि आज देश में हमारी शिक्षा भी गरीब और अमीर में बंट गयी है। मान लिया गया है कि आर्थिक अभावों से जूझ रहे परिवारों के बच्चों की विवशता है कि वे सरकारी स्कूलों में जाएं जहां पढ़ाई लगभग मुफ्त होती है। आर्थिक स्थिति जरा-सी भी सुधरती है तो यह अभिभावक महंगे स्कूलों की ओर रुख कर लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र का यह बंटवारा हमारी प्राथमिक चिंता होनी चाहिए। स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर ही विद्यार्थियों को 'छोटे-बड़े' का अहसास दिलाने वाली हमारी शिक्षा-नीति एक तरह से शिक्षा के अधिकार के हमारे दावों को ही झुठला रही है।

हम देश के हर बच्चे के शिक्षा के अधिकार की बात तो करते हैं, पर किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है इस बारे में शायद सोचना ही नहीं चाह रहे। सन् 2021-22 में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में 10,22,386 सरकारी और 3,35,844 निजी स्कूल हैं। यहां निजी स्कूल का मतलब महंगी पढ़ाई और बेहतर सुविधा है। यह कतई ज़रूरी नहीं है कि महंगी पढ़ाई का मतलब अच्छी पढ़ाई ही हो– हां, इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे और पढ़ाने वाले अभिभावक यह अहसास अवश्य जीते हैं कि उनका स्तर 'ऊंचा' है। शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह के बीमार सोच का पालन उन सबके लिए चिंता की बात होनी चाहिए जो समता-समानता के दर्शन वाले संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं। 'पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया' का नारा देने वाले को इस बात की भी चिंता होनी चाहिए कि 'इंडिया' क्या पढ़ रहा है? कैसी पढ़ाई कर रहा है। दुर्भाग्य से यह चिंता कहीं दिखाई नहीं देती। नीति-आयोग की इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट में हमारे स्कूलों की स्थितियों को तो अच्छे ढंग से दिखाया गया है, पर जिस तरह से यह रिपोर्ट अचर्चित ही रही है, वह हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। आखिर हमें दो तरह की शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? क्यों नहीं देश के हर बच्चे को एक समान और अच्छे स्तर की शिक्षा मिलनी चाहिए? इस बारे में हमारा छोटा-सा पड़ोसी देश नेपाल भी हमें कुछ सिखा सकता है। सुना है नेपाल की नई सरकार ने हाल ही में देश के सारे निजी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। वहां यह व्यवस्था की जा रही है कि सारी शिक्षा सरकारी स्कूलों के माध्यम से दी जाये ताकि सब बच्चे एक जैसे स्तर की शिक्षा पा सकें। शिक्षा का अधिकार जितना ज़रूरी है, उससे कम ज़रूरी नहीं है शिक्षा का समुचित अवसर मिलना। शिक्षा को निजी और सरकारी में बांटने का मतलब अवसर की समानता के अधिकार को नकारना है।

ज़रूरी है कि स्कूली शिक्षा प्रणाली और गुणवत्ता संवर्धन का विश्लेषण करने वाली इस रिपोर्ट पर देश में गहरा और व्यापक चिंतन हो। आज यह सवाल पूछे जाने की आवश्यकता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने का अर्थ घटिया शिक्षा पाना ही क्यों माना जाता है? क्यों नहीं हम सरकारी स्कूलों में ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि हमारे बच्चे गर्व से कहें कि वे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? स्कूलों में पानी हो, बिजली हो, शौचालय हो, अच्छी साफ-सुथरी कक्षाएं हों– और बच्चों को पढ़ाने वाले सक्षम अध्यापक हों, इन अपेक्षाओं को पूरा क्यों नहीं किया जा सकता? क्यों यह नहीं सोचा जाता कि एकल अध्यापक वाले स्कूल में बच्चे उचित शिक्षा कैसे पा सकते हैं?

बात शिक्षा के स्तर की होनी चाहिए। हम विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा-प्रणाली वाला देश होने का दावा तो करते हैं, पर हमें इस बात पर शर्म क्यों नहीं आती कि हमारे स्कूलों में पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा दूसरी कक्षा का पाठ भी अच्छी तरह से क्यों नहीं पढ़ पाता? निजी स्कूल इन और ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं हैं। इसका उत्तर सरकारी स्कूलों को सक्षम बनाना है। पिछले एक अर्से में देश में 42,000 निजी स्कूल खुले हैं और इस दौरान देश के 13 करोड़ सरकारी स्कूल घटकर 12 करोड़ रह गये हैं! यह एक करोड़ स्कूल कहां गायब हो गये? और क्यों गायब हो गये? सवाल बहुत सारे हैं। दुख की बात यह है कि कोई इनका जवाब देने की आवश्यकता नहीं समझ रहा। नीट की परीक्षा में हुई गड़बड़ी निश्चित रूप से एक गंभीर बात है। देश के शिक्षा मंत्री को इस गड़बड़ी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन शिक्षा मंत्री को जिम्मेदारी इस बात की भी लेनी होगी कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण-व्यवस्था इतनी लचर क्यों है? क्यों सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं? क्यों सरकारी स्कूलों में शिक्षा के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है? क्यों स्कूलों में ऊंची कक्षाओं में बच्चों को बनाए रखना एक समस्या है? क्यों दस में से चार बच्चे माध्यमिक शिक्षा पूरी किये बिना ही स्कूल छोड़ देते हैं? इन और ऐसे सवालों के जवाब मांगना उतना ही ज़रूरी है जितना 'नीट' की परीक्षा का पारदर्शी होना।

प्रेरणा

बोझ छोड़ने का हुनर

रेगिस्तान की तपती दोपहर थी। आसमान आग बरसा रहा था और दूर-दूर तक फैली रेत मानो इंसान के भीतर की बेचैनी को भी उजागर कर रही थी। ऐसे ही समय में एक अमीर सौदागर थके हुए कदमों से बाबा कमरुद्दीन के डेरे पर पहुंचा। उसके कपड़े कीमती थे, हाथों में सोने की अंगूठियां चमक रही थीं और उसके पीछे नौकरों की लंबी कतार थी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून का नामोनिशान नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी थकान और दिल में अनकही घुटन थी।

वह बाबा के सामने बैठ गया और बोला, "बाबा, मेरे पास सब कुछ है। दौलत है, हवेलियां हैं, नौकर-चाकर हैं, इज्जत है, लेकिन फिर भी दिल बेचैन रहता है। रातों को नींद नहीं आती। हर समय डर लगा रहता है कि कहीं कुछ छिन न जाए। मुझे सुकून कहां मिलेगा?"

बाबा कमरुद्दीन ने उसकी ओर गौर से देखा। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कोई लंबा उपदेश नहीं दिया। पास रखा एक बड़ा बोरा उठाया, जिसमें भारी पत्थर भरे हुए थे। वह बोरा सौदागर के कंधे पर रखते हुए बोले, "इसे उठाओ और मेरे साथ चलो।"

सौदागर हैरान था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बोरा उठाकर बाबा के पीछे चल पड़ा। शुरुआत में उसे लगा कि यह काम आसान है। आखिर वह एक ताकतवर आदमी था। लेकिन कुछ ही देर बाद धूप तेज़ होने लगी। रेत तपने लगी। गर्म हवा चेहरे पर चाबुक की तरह लग रही थी। बोरे का वजन धीरे-धीरे उसके कंधों को तोड़ने लगा। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। माथे से पसीना बहने लगा।

कुछ दूर चलने के बाद उसने हांफते हुए कहा, "बाबा, यह बोझ बहुत भारी है।"

बाबा ने शांत स्वर में कहा, "थोड़ा और चलो।"

सौदागर फिर चल पड़ा। अब हर कदम उसके लिए मुश्किल था। उसे लग रहा था कि उसकी सांसें टूट जाएंगी। थोड़ी देर बाद वह घुटनों के बल गिर पड़ा और दर्द से कराहते हुए बोला, "अब नहीं चला जाता बाबा। मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जा रहा।"

तब बाबा ने उसकी ओर देखकर कहा, "बोरा नीचे रख दो।"

जैसे ही सौदागर ने बोरा जमीन पर रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर से कोई पहाड़ उतर गया हो। उसके कंधे हल्के हो गए। सांसें सामान्य होने लगीं। चेहरे पर राहत दिखाई देने लगी। वह कुछ क्षण वहीं बैठा रहा और पहली बार उसे भीतर हल्कापन महसूस हुआ।

बाबा उसके पास बैठे और बोले, "जिस तरह यह पत्थरों का बोरा तुझे थका रहा था, उसी तरह तेरी लालच, डर, घमंड और पुरानी शिकायतें तेरी रूह पर रखे हुए पत्थर हैं। तू उन्हें हर वक्त अपने साथ ढोता रहता है। इसलिए तेरी जिंदगी में सुकून नहीं है।"

सौदागर चुपचाप सुनता रहा। बाबा ने रेत की एक मुट्ठी उठाई और उसे कसकर बंद कर लिया। फिर बोले, "देखो, जब मुट्ठी बंद होती है तो रेत को पकड़ने की कोशिश में हाथ में तनाव पैदा होता है। इंसान भी इसी तरह हर चीज़ को पकड़कर रखना चाहता है। दौलत, रिश्ते, मान-सम्मान, गुस्सा, शिकायतें—सब कुछ। वह छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन जितना कसकर पकड़ता है, उतना ही दुखी होता जाता है।"

फिर बाबा ने धीरे-धीरे अपनी मुट्ठी खोल दी। रेत नीचे गिरने लगी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, "जब हाथ खुल जाता है, तो रेत भी गिर जाती है और हाथ भी हल्का हो जाता है। जिंदगी का सुकून पकड़ने में नहीं, छोड़ने में है।"

सौदागर की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी परेशानी बाहर की नहीं, भीतर की थी। वह सारी उम्र दौलत जोड़ने में लगा रहा, लेकिन अपने मन का बोझ उतारना कभी नहीं सीखा। उसे हर समय यह डर रहता था कि कहीं उसका व्यापार कम न हो जाए, कहीं लोग उसका सम्मान करना बंद न कर दें, कहीं कोई उससे आगे न निकल जाए। वह दूसरों की गलतियों को भी वर्षों तक अपने दिल में दबाकर रखता था। बाहर से अमीर था, लेकिन भीतर से थका हुआ और गरीब।

बाबा बोले, "इंसान अक्सर समझता है कि ज्यादा पाने से सुकून मिलेगा। लेकिन सच यह है कि सुकून ज्यादा इकट्ठा करने से नहीं, अनावश्यक बोझ छोड़ने से मिलता है। जिस दिल में नफरत, ईर्ष्या और अहंकार भरा हो, वहां शांति कभी नहीं टिकती।"

रेगिस्तान की हवा अब थोड़ी ठंडी लगने लगी थी। सौदागर ध्यान से बाबा की बातें सुन रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे पहली बार कोई उसके दिल की गांठें खोल रहा हो। बाबा ने कहा, "जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे, जो हर समय अपने दुखों और शिकायतों को ढोते रहते हैं। दूसरे वे, जो माफ करना सीख जाते हैं, छोड़ना सीख जाते हैं। पहले लोग हमेशा थके रहते हैं, जबकि दूसरे लोग कम चीज़ों में भी खुश रहते हैं।"

सौदागर ने धीरे से पूछा, "लेकिन बाबा, छोड़ना इतना आसान कहां होता है?" बाबा मुस्कुराए और बोले, "आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है। जैसे तूने अभी बोरा नीचे रखा, वैसे ही इंसान को अपने भीतर के बोझ भी एक-एक करके नीचे रखने पड़ते हैं। पुरानी तकलीफें, टूटे रिश्तों का दर्द, अपमान की यादें—अगर इन्हें हमेशा उठाए रखोगे तो जिंदगी बोझ बन जाएगी।" सूरज अब ढलने लगा था। आसमान पर हल्की लालिमा फैल गई थी। सौदागर काफी देर तक चुप बैठा रहा। उसके भीतर कुछ बदल रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सुकून किसी महल, खजाने या शोहरत में नहीं छिपा। सुकून उस हल्केपन में है, जब इंसान अपने दिल से अनावश्यक पत्थर हटा देता है।

वह बाबा के कदमों में झुक गया और बोला, "आज तक मैंने दौलत कमाने का हुनर सीखा था, लेकिन आज आपने मुझे हल्का होकर जीने का हुनर सिखा दिया।"

बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, "याद रखो, जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत भरा हुआ खजाना नहीं, बल्कि हल्का दिल होता है। क्योंकि जिस इंसान का दिल हल्का होता है, वही सच में सुकून की नींद सो पाता है।"

उस दिन सौदागर जब वापस लौटा, तो उसके पास वही हवेलियां थीं, वही दौलत थी, वही नौकर थे, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसने पहली बार महसूस किया कि इंसान को थकाने वाला सफर नहीं, बल्कि वह बोझ होता है जिसे वह बेवजह उठाए फिरता है। और जब इंसान छोड़ना सीख जाता है, तभी उसे असली सुकून मिलता है।

खुद को पहचानने की कोशिश में पाकिस्तान

लाहौर में असंख्य स्थानों के बदले गए कई नामों को फिर अपने मूल नामों में बदलने का फैसला कई अर्थों में एक बड़ी घटना है। इसमें ब्रिटिश नाम ही नहीं, हिंदू देवी-देवताओं से जुड़े नाम भी हैं। इनमें कृष्ण नगर, राम गली, धर्मपुरा, लक्ष्मी चौक, संतनगर आदि हैं, जिन्हें विभाजन के बाद इस्लामपुरा, रहमान गली, मुस्तफाबाद आदि कर दिया गया था। कट्टरपंथियों के दबाव में पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज की अध्यक्षता में कैबिनेट के ओर से लिए गए फैसले को रोक लिया गया है। देखना है आगे क्या होता है? वैसे मूल नाम बहाल करने का कारण यह बताया गया था कि लाहौर की सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक विरासत को पुनर्जीवित करना है।

इससे पाकिस्तान के अस्तित्व की बुनियाद ही बदलती दिखती है। क्लासिक इस्लामी नजरिये से 'इस्लामपुरा' को 'कृष्ण नगर' कहना घोर कुफ्र यानी सबसे घृणित काम है। यह पाकिस्तान का ही नाम बदल कर 'पश्चिमी भारत' कर देने जैसा है। यदि पाकिस्तान अपने क्षेत्र की मूल सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक विरासत को महत्व दे रहा है, तो यह बात बहुत दूर तक जा सकती है। इसमें न केवल भारत-विभाजन को व्यर्थ, अनुपयुक्त और अलाभकारी मानने का संकेत है, अपितु स्वयं इस्लामी मान्यताओं को अनुपयुक्त मानना है।

मोरक्को, मिस्र, सऊदी अरब से लेकर ईरान तक में संस्कृति एवं इतिहास को लेकर यह उलझन स्थायी रही है। सबमें समान तत्व जीवन की वास्तविकता और इस्लामी निर्देशों के बीच विरोध ही है। पाकिस्तान में विभाजन के फौरन बाद ही विचारशील लोग असहज होने लगे थे। वहां संविधान बनने में नौ वर्ष लगे, जिसमें पाकिस्तान को 'इस्लामी रिपब्लिक' कहा गया। पर फिर छह वर्ष में ही संविधान बदल दिया गया। 1962 में बने दूसरे संविधान में देश के नाम से 'इस्लामी' हटा कर केवल 'रिपब्लिक आफ पाकिस्तान' कर दिया गया। फिर इस्लामी शब्द जोड़ा गया। 11 वर्ष बाद तीसरा संविधान आया, जिसमें इस्लाम को 'राजकीय मजहब' घोषित किया गया। जिया उल हक और फिर परवेज मुशर्रफ ने संविधान का और इस्लामीकरण किया। मुशर्रफ ने तो 'जिहाद' को पाकिस्तान की विदेश नीति भी बताया। इसके बाद अब फिर मूल सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक विरासत की ओर लौटने की कोशिश इसकी स्वीकृति है कि अधिक से अधिक इस्लामीकरण मनुष्य की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक प्यास को उपेक्षित करता है। पाकिस्तान की इस विडंबना का एक आकलन नोबेल पुरस्कृत लेखक वीएस नायपाल ने वहां रहकर किया था। अपनी पुस्तकों 'अमंग द बिलीवर्स' और 'बियांड बिलीफ' में उन्होंने पाकिस्तानी मानस की दुविधा को दिखाया। उन्होंने ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया को लेकर भी यह आकलन किया था कि हर कहीं इस्लामी प्रतिबद्धता और मानवीय स्वतंत्रता के बीच स्थायी तनाव है। इस्लामी बंधन को बलपूर्वक बनाए रखना होता है, वरना उसका टिकना असंभव है।

प्रख्यात लेखक नीरद सी. चौधरी ने भी लिखा था कि पाकिस्तान एक विनष्ट उद्देश्य के लिए लड़ते रहने को विवश है, अन्यथा वह खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब किसी मुस्लिम देश में सब कुछ शरीयत से नहीं चलता, जबकि यही इस्लाम की मूल टेक है। उनके अवलोकन के बाद 64 वर्षों में मुस्लिम जगत ने और विशाल अनुभव पा लिया है। पेट्रो-डालर, ईरान में खुमैनी क्रांति, तालिबान, अलकायदा, इस्लामिक स्टेट आदि का दशकों चला जिहाद और अब ईरान की दुर्दशा, सभी अनुभव संकेत करते हैं कि राजनीतिक इस्लाम का कोई भविष्य नहीं है। इसीलिए सऊदी में भी इस्लाम से पहले के स्थानों, प्रतीकों को ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत के रूप में स्थापित किया गया है। वहां सिनेमा, संगीत, लड़कियों के लिए फुटबाल की अनुमति, शिक्षा में योगाभ्यास आदि को स्थान दिया जा चुका है। यह सब अनायास भी हो रहा है और सुविचारित भी। संख्यात्मक रूप से मुस्लिम बढ़ रहे हैं, पर अंदर इस्लाम से मोहभंग भी बढ़ रहा है। चाहे अभी संख्या में कम हों, पर हर कहीं विचारशील मुस्लिम समझ चुके हैं कि 14 सौ साल पहले के पिछड़े, संकीर्ण अरब क्षेत्र में दिए गए कायदे, वर्जनाएं और लक्ष्य दरअसल जीवन और प्रकृति से दूर हैं।

ऐतिहासिक रूप से भारतीय मनीषा से जुड़े होने के कारण अनेक पाकिस्तानी कभी नहीं तय कर पाए कि एक राष्ट्र के रूप में वे कौन है? कहां से जुड़े हैं? खुद पाकिस्तान में जिन्ना और इकबाल की इसे लेकर अलग-अलग समझ थी कि इस्लाम को जीवन में कैसे उतारा जाए? वहां हर फिरका दूसरे को 'काफिर' कहता है। केवल भारत-विरोध पाकिस्तानी लोगों को जोड़ने की चीज रही है, पर वह एक नकारात्मक भावना है। इससे पाकिस्तानी समाज की उन्नति असंभव है। यह भविष्य ही बताएगा कि क्या पाकिस्तानी नेतृत्व सच स्वीकार करने की ओर बढ़ रहा है, किंतु यदि ऐसा हुआ तो भारत विभाजन का औचित्य कभी भी एक झटके में खत्म हो सकता है, जैसे कम्युनिज्म की सच्चाई स्वीकार करते ही पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का भेद खत्म हो गया था। पाकिस्तान में जो हो रहा है, उसकी परिणति जर्मनी वाली होना संभव है, क्योंकि यदि पाकिस्तानी उच्च वर्ग इस्लाम से मुंह मोड़ ले तो, आम जन मूल भारतीय समाज के प्रति स्वतः खिंचा आएगा, जिसकी सभ्यता और संस्कृति का वह सहज अंग रही है। पंजाब, सिंध, और बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग को 1946 तक कोई समर्थन नहीं था।

उसकी मांग मुख्यतः अलीगढ़, कलकत्ता और बंबई के मुस्लिम नेताओं ने की थी। पंजाब और सिंध के मुसलमानों को तो विभाजन एक आकस्मिक नियामत के रूप में मिला। फिर उन्हें अपनी ही गौरवशाली संस्कृति, इतिहास, साहित्य और समाज से घृणा करना सिखाया गया। आखिर भारत-विरोधी नीतियों से पाकिस्तानी पंजाब के लोगों को अब तक क्या हासिल हुआ? अभी यह कहना कठिन है कि इस्लाम को अपना आधार बनाना असल में गले का तौक हो गया है, पर यह तय है कि इस्लाम की अपनी मूल पहचान हटाते ही पाकिस्तान का अस्वाभाविक विलगाव जाता रहेगा। फिर क्या होगा, यह अल्लाह जानता है।

अभियान

बिल्व पर्वत की दिव्य शक्ति: मां मनसा देवी के दरबार में क्यों नहीं लौटता कोई खाली हाथ

भारत की धार्मिक परंपरा में कुछ ऐसे तीर्थ स्थल हैं, जिनकी महिमा केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वहां पहुंचने वाला हर श्रद्धालु स्वयं किसी अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव को महसूस करता है। उत्तराखंड की पावन धरती पर स्थित हरिद्वार भी ऐसा ही एक तीर्थ है, जहां आस्था गंगा की धारा की तरह निरंतर बहती रहती है। हरिद्वार केवल एक शहर नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा का केंद्र है। यहां का हर घाट, हर मंदिर और हर घंटी भक्तों को ईश्वर के और करीब ले जाती है। इन्हीं पवित्र स्थलों में से एक है बिल्व पर्वत पर स्थित मां मनसा देवी का चमत्कारी मंदिर, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं और विश्वास के साथ लौटते हैं कि मां उनकी झोली जरूर भरेंगी।

हरिद्वार की यात्रा पर आने वाला शायद ही कोई ऐसा श्रद्धालु हो, जो मां मनसा देवी के दर्शन किए बिना वापस लौटना चाहे। ऊंचे पर्वत पर स्थित यह मंदिर दूर से ही श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे-जैसे भक्त पर्वत की ओर बढ़ते हैं, वैसे-वैसे उनके भीतर भक्ति की भावना और गहरी होती जाती है। नीचे बहती मां गंगा की निर्मल धारा, मंदिरों की गूंजती घंटियां और पर्वतों के बीच फैली आध्यात्मिक ऊर्जा मन को एक अलग ही शांति प्रदान करती है। यही कारण है कि यहां पहुंचने वाला हर व्यक्ति अपने भीतर किसी अनजानी शक्ति का अनुभव करता है।

मां मनसा देवी को शक्ति का दिव्य स्वरूप माना जाता है। "मनसा" शब्द का अर्थ ही मन की इच्छा से जुड़ा हुआ है। धार्मिक मान्यता है कि मां अपने भक्तों के मन की हर बात जान लेती हैं और सच्चे मन से मांगी गई प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करती हैं। यही कारण है कि यह मंदिर मनोकामना पूर्ण करने वाले सिद्धपीठों में गिना जाता है। श्रद्धालु यहां आकर लाल धागा या मौली बांधते हैं और अपनी इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। जब उनकी मुराद पूरी हो जाती है, तो वे दोबारा आकर उस धागे को खोलते हैं। वर्षों पुरानी यह परंपरा आज भी भक्तों के अटूट विश्वास का प्रतीक बनी हुई है।

मां मनसा देवी मंदिर का इतिहास भी अत्यंत प्राचीन और रहस्यमयी माना जाता है। कहा जाता है कि वर्तमान मंदिर का निर्माण वर्ष 1811 से 1815 के बीच राजा गोपाल सिंह द्वारा करवाया गया था। हालांकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान की पवित्रता हजारों वर्षों से मानी जाती रही है। पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत कलश को लेकर संघर्ष हुआ था, तब अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर जिन स्थानों पर गिरी थीं, उनमें हरिद्वार भी शामिल था। यही वजह है कि हरिद्वार को कुंभ नगरी कहा जाता है और यहां स्थित मां मनसा देवी का मंदिर विशेष रूप से पूजनीय माना जाता है।

मंदिर में स्थापित मां की प्रतिमाएं भक्तों के मन में विशेष श्रद्धा उत्पन्न करती हैं। यहां मां की दो प्रमुख मूर्तियां विराजमान हैं। एक प्रतिमा में मां के तीन मुख और पांच भुजाएं दिखाई देती हैं, जबकि दूसरी प्रतिमा में मां आठ भुजाओं के साथ सर्प पर विराजमान हैं। मां का यह स्वरूप शक्ति, रक्षा और कृपा का प्रतीक माना जाता है। जब श्रद्धालु मां के इन दिव्य रूपों के दर्शन करते हैं, तो उनके मन में विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है कि मां हर संकट से उनकी रक्षा करेंगी।

इस मंदिर से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध मान्यता संतान प्राप्ति को लेकर है। कहा जाता है कि जो दंपति संतान सुख से वंचित होते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ मां के चरणों में प्रार्थना करते हैं, उनकी सूनी गोद भर जाती है। देशभर से हजारों दंपति केवल इसी आस्था के साथ यहां आते हैं। कई श्रद्धालु बताते हैं कि वर्षों तक संतान न होने के बाद मां मनसा देवी की कृपा से उनके घर में बच्चे की किलकारी गूंजी। यही कारण है कि यह मंदिर निःसंतान दंपतियों के लिए विशेष आस्था का केंद्र बन चुका है।

इतना ही नहीं, सुहागिन महिलाएं भी यहां अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए विशेष पूजा करती हैं। सावन और नवरात्रि के दौरान यहां महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है। लाल चुनरी, नारियल, फूल और सिंदूर लेकर महिलाएं मां के दरबार में पहुंचती हैं और अपने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। मंदिर परिसर में गूंजते "जय मां मनसा" के जयकारे पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं।

नवरात्रि के दौरान मां मनसा देवी मंदिर की भव्यता देखने लायक होती है। मंदिर को रंग-बिरंगी रोशनियों और फूलों से सजाया जाता है। सुबह से लेकर देर रात तक भक्तों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। भजन-कीर्तन और घंटियों की ध्वनि पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। ऐसा लगता है मानो पूरा हरिद्वार मां की भक्ति में डूब गया हो।

मां मनसा देवी का मंदिर केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता के कारण भी बेहद आकर्षक माना जाता है। बिल्व पर्वत की ऊंचाई से दिखाई देने वाला हरिद्वार का दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। नीचे बहती गंगा की धारा, दूर तक फैले घाट और मंदिरों के शिखर मन को अद्भुत शांति प्रदान करते हैं। कई श्रद्धालु यहां केवल दर्शन के लिए ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति पाने के लिए भी आते हैं। कहा जाता है कि मां के दरबार में कुछ समय बिताने मात्र से मन की बेचैनी दूर होने लगती है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां मनसा देवी को नागों की देवी भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं में उनका संबंध भगवान शिव से बताया गया है। कहा जाता है कि वे भगवान शिव के मन से उत्पन्न हुई थीं। यही कारण है कि उनका संबंध शिव शक्ति परंपरा से भी जोड़ा जाता है। कई श्रद्धालु नाग दोष, ग्रह बाधा और जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिए यहां विशेष पूजा करवाते हैं। हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मां मनसा देवी और मां चंडी देवी के दर्शन बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इन दोनों शक्तिपीठों के दर्शन किए बिना हरिद्वार की यात्रा अधूरी रहती है। यही कारण है कि सालभर यहां भक्तों का तांता लगा रहता है। विशेष रूप से कुंभ और अर्धकुंभ के दौरान यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। समय के साथ मंदिर में कई आधुनिक सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। अब श्रद्धालु रोपवे की सहायता से आसानी से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। हालांकि आज भी कई भक्त पैदल चढ़ाई करना अधिक पुण्यदायी मानते हैं। वे "जय माता दी" के जयकारे लगाते हुए पर्वत की चढ़ाई करते हैं और इसे अपनी श्रद्धा की परीक्षा मानते हैं। कठिन चढ़ाई के बावजूद उनके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि मां के दर्शन की खुशी दिखाई देती है।

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान तनाव, अकेलेपन और मानसिक परेशानियों से घिरता जा रहा है। ऐसे समय में मां मनसा देवी का यह पवित्र दरबार लोगों को उम्मीद और आस्था की नई रोशनी देता है। यहां आने वाला हर भक्त अपने भीतर एक अलग ऊर्जा महसूस करता है। कोई यहां अपनी अधूरी इच्छा लेकर आता है, तो कोई टूटे हुए मन को संभालने के लिए। लेकिन मां के दरबार से लौटते समय उनके चेहरे पर एक अलग ही संतोष दिखाई देता है।

मां मनसा देवी का मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, उम्मीद और विश्वास का प्रतीक है। यहां की हवा में भक्ति है, वातावरण में दिव्यता है और हर पत्थर में श्रद्धा की कहानी छिपी हुई है। सदियों बीत जाने के बाद भी इस मंदिर की महिमा कम नहीं हुई। मां के दरबार में आने वाला हर भक्त यही महसूस करता है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ मांगी गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब श्रद्धालु मां के चरणों में सिर झुकाता है, तो उसके भीतर एक नई आशा जन्म लेती है। उसे लगता है कि अब उसकी परेशानियां मां के हाथों में हैं और मां उसे कभी निराश नहीं करेंगी। यही विश्वास इस मंदिर की सबसे बड़ी शक्ति है। मां मनसा देवी अपने भक्तों के जीवन में ऐसा प्रकाश भर देती हैं, जो कठिन से कठिन समय में भी बुझता नहीं। शायद यही कारण है कि हरिद्वार का यह पवित्र मंदिर आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ बसता है, जैसे सदियों पहले बसता था। मां के दरबार में पहुंचने वाला हर भक्त यही कहता है कि यहां केवल मनोकामनाएं ही पूरी नहीं होतीं, बल्कि टूटे हुए मन को भी नई उम्मीद मिल जाती है।

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गांधीनगर जिले में 340 करोड़ रुपए के 84 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

- 2029 तक गांधीनगर जिले के प्रत्येक गांव में एक-एक पुस्तकालय और उद्यान के साथ ही सुंदर मनोरंजन स्थल उपलब्ध होंगे
- आज 'गुजरात विकास मॉडल' कश्मीर से कन्याकुमारी और सोमनाथ से गंगासागर तक पूरे देश में स्वीकृत
- राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार विदेशी घुसपैठियों को चुन-चुनकर देश से बाहर निकालने को प्रतिबद्ध
- 1857 के विद्रोह को 'स्वतंत्रता संग्राम' का नाम देने वाले वीर सावरकर ने सामाजिक क्षेत्र में अस्पृश्यता निवारण और दलितों के लिए पतित पावन मंदिर के निर्माण जैसे क्रांतिकारी कार्य किए

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- गांधीनगर को 'हरित लोकसभा' बनाने के लिए 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य
- गांधीनगर में बनेगी देश की सबसे बड़ी और आधुनिक 'नमो सेंट्रल लाइब्रेरी' : बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान
- केंद्रीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में गांधीनगर को देश का सबसे विकसित क्षेत्र बनाने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध

कलोल और गांधीनगर उत्तर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में जीयूडीए, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में अनेक विकास कार्यों की भेंट : निजी कंपनियों के सीएसआर फंड से ग्रामीण पुस्तकालयों का निर्माण और तालाबों का सौंदर्यीकरण

गांधीनगर : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुरुवार को गांधीनगर जिले के सोनीपुर गांव में कलोल और गांधीनगर उत्तर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 340 करोड़ रुपए के 84 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम से पूर्व दोनों महानुभावों ने पौधरोपण भी किया।

आय आयोजित इन कार्यक्रमों में सरकारी विभागों के साथ ही निजी कंपनियों के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) फंड के सहयोग से पंचायत तथा सड़क एवं भवन विभाग के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इसके अलावा, रेलवे के अंडरब्रिज के कार्यों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया गया।

इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्य में बह रही विकास की गंगा का श्रेय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को देते हुए कहा कि गांधीनगर संसदीय क्षेत्र को देश का सबसे विकसित क्षेत्र बनाने के दृढ़ संकल्प के साथ विकास कार्यों की बौछार शुरू हो चुकी है। गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में आज 340 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण किया गया है। इसके साथ ही, पिछले 10 दिनों में करीब 1200 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्य शुरू किए गए हैं। जो दर्शाता है कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा उद्योग समूहों के सीएसआर फंड की सहायता से गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास तेज किए गए हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर और सुविधासंपन्न बनाने के विजन का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केवल वित्तीय कोष ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हर गांव को आत्मनिर्भर बनाना और सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित करना सरकार की प्राथमिकता है। हर नागरिक सम्मानपूर्वक जीवन जिए, इसके लिए गांवों में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और शुद्ध पेयजल की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। अधिक से अधिक युवाओं में पठन-पाठन की आदत विकसित हो, इसके लिए ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना की गई है, जिसे गांधीनगर की लाइब्रेरी के साथ जोड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, वर्ष 2029 तक गांधीनगर के हर गांव में एक-एक पुस्तकालय और उद्यान के साथ ही सुंदर मनोरंजन स्थल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विकास-उन्मुख नीतियों को ध्यान में रखकर ही नागरिकों ने उन्हें सत्ता की कमान सौंपी है। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान जो 'गुजरात विकास मॉडल' दिया था, वह आज कश्मीर से कन्याकुमारी और सोमनाथ से गंगासागर तक पूरे देश में स्वीकृत हो गया है।

हाल ही में पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग का काम तेजी से चल रहा है। जहां पहले की सरकार के शासन में रोजाना घुसपैठ होती थी, वहां अब घुसपैठिए स्वयं अपनी मर्जी से वापस जा रहे हैं। सरकार ने डिटेंशन सेंटर भी बनाए हैं। जो घुसपैठिए अपनी मर्जी से देश छोड़ेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी और सरकार उन्हें मदद भी करेगी।

श्री शाह ने दृढ़तापूर्वक कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर घुसपैठियों को चुन-चुनकर देश से बाहर निकालने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डेमोग्राफिक चेंज यानी जनसांख्यिकी परिवर्तन पर एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, जो असामान्य कारणों से पूरे देश में हो रहे डेमोग्राफिक परिवर्तनों की जांच करके एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आवश्यकता पड़ने पर कठोर कानून भी बनाए जाएंगे।

वीर सावरकर जी की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए श्री शाह ने कहा कि वे एक ऐसे राष्ट्रभक्त थे, जिन्हें देश का हर बालक आदरपूर्वक 'वीर सावरकर' के नाम से जानता है। आजादी के आंदोलन के दौरान उन्हें दोहरी उम्रकैद की सजा हुई थी। कालापानी की सजा के दौरान जेल की दीवारों पर अपने लहू से कविताएं लिखने वाले और 1857 के विद्रोह को 'स्वतंत्रता संग्राम' का नाम देने वाले सावरकर जी ने सामाजिक क्षेत्र में अस्पृश्यता निवारण और दलितों के लिए पतित पावन मंदिर का निर्माण जैसे क्रांतिकारी कार्य किए थे।

अंत में, उन्होंने एक बार फिर गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र को देश का सबसे विकसित निर्वाचन क्षेत्र बनाने का इरादा व्यक्त किया और सभी नागरिकों से इस विकास यात्रा में शामिल होने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गांधीनगर संसदीय क्षेत्र को देश का सबसे विकसित क्षेत्र बनाने के लक्ष्य के साथ आज गांधीनगर उत्तर विधानसभा क्षेत्र और कलोल तहसील में 340 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। प्रखर राष्ट्रभक्त वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में सोनीपुर तालाब का शिलान्यास किया गया।

ग्रामीण नागरिकों की सुख-सुविधा में वृद्धि करने वाली विभिन्न परियोजनाएं जनता को समर्पित की गईं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा 10 दिन पहले ही 620 करोड़ रुपए के कार्यों की मंजूरी देने के बाद, उनकी ओर से गांधीनगर जिले के नागरिकों को यह लगातार दूसरी बड़ी सौगात मिली है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ हवा-पानी की विरासत देने के लिए गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में 1 करोड़ पौधे लगाने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आगामी समय में डिजिटल और सांस्कृतिक साक्षरता को ध्यान में रखकर टोयोटा किर्लोस्कर मोटर, जिला प्रशासन, सीएसआर फंड और दानदाताओं के सहयोग से 20 गांवों में लाइब्रेरी स्थापित करने की योजना है, जिसके अंतर्गत आज तीन गांवों में महान साहित्यकारों कवि नर्मद, आद्यकवि दलपतराम और गोवर्धनराम त्रिपाठी के नाम पर आधुनिक पुस्तकालय शुरू किए गए हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने आगे कहा कि गांधीनगर में देश की सबसे बड़ी और आधुनिक 'नमो सेंट्रल लाइब्रेरी' बनाने के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं, गुजरात में पिछले दो वर्षों में 135 नए तहसील पुस्तकालयों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, उन्होंने यह विश्वास भी व्यक्त किया कि जलुंद गांव में नए स्वास्थ्य उपकेंद्र के निर्माण माताओं और बहनों को स्थानीय स्तर पर ही चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने आगे कहा कि डबल इंजन सरकार का लक्ष्य केवल भौतिक संरचनाएं खड़ी करना ही नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में 'ईज ऑफ लिविंग' यानी जीवन सुगमता को बेहतर बनाकर वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के स्वप्न को साकार करना है।

इस अवसर पर गांधीनगर उत्तर की विधायक श्रीमती रीटाबेन पटेल ने स्वागत भाषण में आंकड़ों के साथ राज्य सरकार के विभिन्न विकास कार्यों की रूपरेखा पेश की।

कार्यक्रम में गांधीनगर दक्षिण के विधायक श्री अल्पेश ठाकोर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेशभाई पटेल, जिला कलेक्टर श्री रवींद्र खटाले, जिला विकास अधिकारी श्री बी.जे. पटेल, सोनीपुर गांव के सरपंच और पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

इंजीनियरिंग वर्कशॉप साबरमती में 'भगवद गीता' के ज्ञान से कार्यस्थल के तनाव प्रबंधन पर विशेष सत्र आयोजित

रेल कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य और प्रभावी तनाव प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए, पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल द्वारा 28 मई 2026 को साबरमती स्थित इंजीनियरिंग वर्कशॉप में "परसीव्ड स्ट्रेस एंड कोपिंग विद द हेल्प ऑफ भगवद गीता" (तनाव और भगवद गीता की सहायता से उसका सामना करना) विषय पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया।

रेलवे संचालन और इंजीनियरिंग के अत्यधिक दबाव वाले माहौल में मानसिक लचीलापन और संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक है। इसी महत्वपूर्ण आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अहमदाबाद मंडल के अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (ACMS/A&H) डॉ. मनोजकुमार देव द्वारा एक संवादात्मक (इंटरैक्टिव) व्याख्यान दिया गया। इस कार्यशाला में लगभग 30 वरिष्ठ अधीनस्थों और अधिकारियों ने भाग लिया।

सत्र के दौरान, डॉ. देव ने तनाव से जुड़े

आधुनिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और भगवद गीता के व्यावहारिक एवं प्राचीन ज्ञान के बीच के अंतर को बेहद सुगमता से पाटा। विशिष्ट श्लोकों का संदर्भ देते हुए, उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि कैसे ये शिक्षाएं रेल कर्मियों को कार्यस्थल के दबाव को देखने के नजरिए में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर सकती हैं।

कार्यशाला के मुख्य बिंदु:

- व्यावहारिक रणनीतियाँ: प्रतिभागियों को दैनिक व्यावसायिक चुनौतियों से निपटने के लिए व्यावहारिक तरीकों से अवगत कराया गया।
- मानसिक दृढ़ता: गंभीर रेलवे संचालन के दौरान मानसिक शांति और स्पष्टता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया।
- तनाव प्रबंधन का समग्र दृष्टिकोण: कार्यस्थल की आधुनिक चुनौतियों और तनाव को दूर करने के लिए पारंपरिक ज्ञान का समावेश।

यह पहल अहमदाबाद मंडल की अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों के समग्र स्वास्थ्य एवं भावनात्मक कल्याण के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंडल द्वारा तकनीकी दक्षता के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य एवं आंतरिक सशक्तिकरण पर भी विशेष बल दिया जा रहा है, ताकि कर्मचारी अधिक प्रभावी एवं समर्पित रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर सकें।

सरखेज-धोलेरा नई सेमी हाई स्पीड रेलवे ब्रॉड गेज डबल लाइन प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन हेतु बैठक आयोजित

पश्चिम रेलवे अहमदाबाद की सर्वे एवं निर्माण संस्था ने आज (28.05.2026) सरखेज-धोलेरा नई सेमी हाई स्पीड रेलवे ब्रॉड गेज डबल लाइन प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के विषय में इच्छुक बीडर्स के साथ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय स्थित कांफ्रेंस हॉल में एक बैठक आयोजित कीI पश्चिम रेलवे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस प्रोजेक्ट में चीफ इंजीनियर कमलेश कुमार, चीफ इलेक्टिकल इंजीनियर आर डी मीना, Dy CSTE रतन बासु व निर्माण विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थेI

मीटिंग की शुरुआत में प्रशांत सिंह, डिप्टी चीफ इंजीनियर ने पॉवर पॉइंट के माध्यम से प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ कियाI प्रोजेक्ट की निर्माण निविदा में रुचि रखने वाले सिविल, इलेक्ट्रिकल तथा S & T (सिग्नल एवं दूरसंचार) क्षेत्रों की 20 से अधिक फर्मों ने भागेदारी की। जिसमें लार्सेन & टुब्रो, अफकोन्स इन्फ्रा, KPTL, HOG प्रोजेक्ट,

मिराल इन्फ्रा, खोडल कारपोरेशन, गंगा कंस्ट्रक्शन, नीलकंठ इन्फ्रा, सुभाष इन्फ्रा आदि फर्मों के प्रतिनिधियों ने प्रोजेक्ट कार्यान्वयन को बेहतर करने के लिये अपने- अपने सुझाव रखेI

बैठक में परियोजना के कार्यान्वयन, पैकेजिंग एवं तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके अंतर्गत सिविल, ट्रेक, ट्रैक्शन व S&T के टेंडर व इंटरफ़ेस कार्यों, डिज़ाइन डिटेल्स के कांट्रेक्ट जैसे विषय पर चर्चा की गईI इसके अलावा कई फर्मों ने वर्चुअल माध्यम से से भी भगीदारी कीI इस दौरान पश्चिम रेलवे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) प्रदीप गुप्ता ने बताया इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य परियोजना का सफल एवं प्रभावी कार्यान्वयन करना हैI इच्छुक बीडर्स के सुझावों पर विचार करने के उपरांत प्रोजेक्ट कार्यान्वयन हेतु EPC टेंडर फ्लोट (float) किया जायेगाI करीब 134 किलोमीटर लंबी यह नई दोहरी रेल लाइन अहमदाबाद, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (SIR), आगामी धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तथा लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (National Maritime Heritage Complex) को अत्याधुनिक रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। परियोजना की डिज़ाइन गति 220 किमी प्रति घंटा तथा परिचालन गति 200 किमी प्रति घंटा निर्धारित की गई है। कॉरिडोर पर कुल 11 स्टेशन विकसित किए जाएंगे। परियोजना के अंतर्गत 3 मेगा पुल, 74 किलोमीटर वायाडक्ट, 39 रोड अंडर ब्रिज तथा 2 रेल ओवर रेल ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। कुल ट्रैक लंबाई लगभग 293 किलोमीटर होगी। परियोजना को अगले 4 वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लगभग 20,667 करोड़ की लागत वाली यह परियोजना भारतीय रेलवे की पहली स्वदेशी तकनीक आधारित सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना होगी, जिस पर भविष्य में नमो भारत ट्रेनों का संचालन किया जाएगा।

यह परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप विकसित की जा रही है, जिसका उद्देश्य मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी को मजबूत करना तथा भारत की लॉजिस्टिक दक्षता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। यह कॉरिडोर गुजरात को आधुनिक, हरित एवं उच्च गति परिवहन अवसंरचना के नए युग में प्रवेश कराने वाली ऐतिहासिक पहल सिद्ध होगा।

सोना वायदा 1857 रुपये और चांदी वायदा 4462 रुपये लुढ़काः क्रूड ऑयल वायदा में 222 रुपये का ऊछाल

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 79116.82 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 4897.71 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 74219.11 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 455.04 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 3602.17 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा 155627 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 155651 रुपये और नीचे में 153551 रुपये पर पहुंचकर, 155627 रुपये के पिछले बंद के सामने 1857 रुपये या 1.19 फीसदी घटकर 153770 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-गिनी मई वायदा 975 रुपये या 0.78 फीसदी लुढ़ककर 123316 रुपये प्रति 8 ग्राम बोला गया। गोल्ड-पेटल मई वायदा 105 रुपये या 0.67 फीसदी लुढ़ककर 15515 रुपये प्रति 1 ग्राम बोला गया। सोना-मिनी जून वायदा सत्र के आरंभ में 153768 रुपये के भाव पर खूलकर, 157751 रुपये के दिन के उच्च और 153149 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 1935 रुपये या 1.25 फीसदी लुढ़ककर 153326 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-टेन मई वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 154691 रुपये के भाव पर खूलकर, 155240 रुपये के दिन के उच्च और 153402 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 155240 रुपये के पिछले बंद के सामने 1589 रुपये या 1.02 फीसदी लुढ़ककर 153651 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया।

चांदी के वायदाओं में चांदी जुलाई वायदा 261561 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 262389 रुपये और नीचे में 261013 रुपये पर पहुंचकर, 266212 रुपये के पिछले बंद के सामने 4462 रुपये या 1.68 फीसदी घटकर 261750 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी जून वायदा 4576 रुपये

या 1.69 फीसदी औंधकर 266101 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि चांदी-माइक्रो जून वायदा 4578 रुपये या 1.69 फीसदी की गिरावट के साथ 266141 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था।

मेटल वर्ग में 422.13 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मई वायदा 4.5 रुपये या 0.34 फीसदी की मजबूती के साथ 1323.55 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि जस्ता मई वायदा 1.45 रुपये या 0.39 फीसदी तेज होकर किलो बोला गया। इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 814.29 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल जून वायदा 8838 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 8900 रुपये और नीचे में 8703 रुपये पर पहुंचकर, 222 रुपये या 2.58 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 8822 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जून वायदा 219 रुपये या 2.55 फीसदी की बढ़त के साथ 8821 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस जून वायदा 298.6 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 300.8 रुपये और नीचे में 297 रुपये पर पहुंचकर, 301.3 रुपये के पिछले बंद के सामने 1.5 रुपये या 0.5 फीसदी घटकर 299.8 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी जून वायदा 1.5 रुपये या 0.5 फीसदी गिरकर 299.8 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ। कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 2517.11 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 1085.06 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 315.02 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 49.58 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 0.93 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 56.59 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 417.37 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 393.47 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 9770 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 67244 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 20437 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 329474 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 48060 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 10826 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 27993 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 92885 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 15485 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 21278 लोट के स्तर पर था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल जून 10000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 33.9 रुपये की बढ़त के साथ 173.8 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जून 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 65 पैसे की नरमी के साथ 16.25 रुपये हुआ।

सोना जून 170000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 94.5 रुपये की गिरावट के साथ 490 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जून 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 457 रुपये की गिरावट के साथ 2410 रुपये हुआ। तांबा जून 1400 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 67 पैसे के सुधार के साथ 14.13 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल जून 7500 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 27.2 रुपये की गिरावट के साथ 69 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जून 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 45 पैसे के सुधार के साथ 16.15 रुपये हुआ। सोना जून 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 295.5 रुपये की बढ़त के साथ 972.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जून 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 228.5 रुपये की बढ़त के साथ 607.5 रुपये हुआ। तांबा जून 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 74 पैसे की नरमी के साथ 13.2 रुपये हुआ।

कमोडिटी वायदाओं में 4897.71 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 74219.11 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 3602.17 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार

"उजालों का आख़िरी मुसाफ़िर चला गया": बशीर बद्र के जाने से ख़ामोश हुई ग़ज़लों की वह आवाज़, जो सदियों तक गूंजती रहेगी

भोपाल। उर्दू अदब की दुनिया गुरुवार को उस गहरे सन्नाटे में डूब गई, जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं। ग़ज़लों को आम आदमी की ज़ुबान बनाने वाले महान शायर Bashir Badr अब इस दुनिया में नहीं रहे। 91 वर्ष की उम्र में भोपाल में उन्होंने आख़िरी सांस ली। वह लंबे समय से डिमेंशिया जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनके निधन की खबर सामने आते ही साहित्यिक जगत, मुशायरों की दुनिया, राजनीतिक गलियारों और करोड़ों प्रशंसकों के बीच शोक की लहर दौड़ गई। ऐसा लगा मानो हिंदुस्तानी तहज़ीब की वह नरम और मोहब्बत भरी आवाज़ अचानक ख़ामोश हो गई हो, जिसने दशकों तक लोगों के दिलों को शब्द दिए।

बशीर बद्र केवल एक शायर नहीं थे, बल्कि वे उस एहसास का नाम थे जिसने ग़ज़ल को महलों और नवाबी दरबारों से निकालकर आम लोगों की चौपाल, गलियों, चाय की दुकानों और दिलों तक पहुंचा दिया। उनकी शायरी में कोई बनावटीपन नहीं था। उसमें मोहब्बत थी, दर्द था, जुदाई थी, तन्हाई थी, टूटते रिश्तों की खामोशी थी और इंसानी ज़िंदगी की गहरी सच्चाइयां थीं। यही वजह रही कि उनके शेर किताबों से ज्यादा लोगों की ज़ुबान पर ज़िंदा रहे।

"मुसाफ़िर हैं हम भी मुसाफ़िर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाक़ात होगी"

उनका यह मशहूर शेर आज उनके चाहने वालों की आंखों में आंसू बनकर उतर आया है। ऐसा लग रहा है मानो वह जाते-जाते खुद अपनी विदाई लिख गए हों।

अगर उर्दू शायरी में लोकप्रियता को पैमाना माना जाए तो जिगर मुरादाबादी, फिराक़ गोरखपुरी और दुष्यंत कुमार के बाद जिस शायर के सबसे ज्यादा अशआर लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बने, वह नाम बशीर बद्र का ही था। उनके कम से कम दो दर्जन शेर ऐसे हैं जो सरहदों और वक़्त की सीमाओं को पार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक, आम इंसान से लेकर बड़े राजनीतिक नेता तक, हर किसी की ज़ुबान पर कभी न कभी बशीर बद्र का कोई न कोई शेर ज़रूर आया।

साल 1935 में उत्तर प्रदेश के Ayodhya में जन्मे बशीर बद्र ने उस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वातावरण में आंखें खोलीं, जिसने उनकी संवेदनशीलता को गहराई दी। शुरुआती

शिक्षा अयोध्या में हुई, लेकिन उनकी साहित्यिक पहचान को असली दिशा मिली Aligarh Muslim University में। यहीं से उन्होंने बी.ए., एम.ए. और पीएचडी की डिग्रियां हासिल कीं। अलीगढ़ का अदबी माहौल उनके भीतर छिपे शायर को शब्द देता चला गया। बाद में उन्होंने मेरठ के एक कॉलेज में उर्दू के प्रोफेसर के रूप में लगभग सत्रह वर्षों तक अध्यापन किया।

उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मोड़ 1987 के मेरठ दंगों के दौरान आया। वह हादसा केवल एक इंसान के घर के जलने का नहीं था, बल्कि एक शायर की पूरी दुनिया राख हो जाने जैसा था। दंगों की आग में उनका घर, उनकी दुर्लभ किताबें और वर्षों की मेहनत से लिखी गई कई ग़ज़लें जलकर खत्म हो गईं। इस घटना ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने मेरठ छोड़ दिया, लेकिन उस दर्द की राख उनकी शायरी में हमेशा जलती रही। शायद यही वजह है कि उनके अशआर सीधे दिल में उतरते थे, क्योंकि वे सिर्फ लिखे नहीं गए थे, बल्कि जीए गए थे।

जिस दौर में उर्दू ग़ज़लें भारी-भरकम और मुश्किल अल्फ़ाज़ों से भरी होती थीं, उस समय बशीर बद्र ने शायरी को आसान और बोलचाल की भाषा दी। उन्होंने वही शब्द चुने जो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। उनकी ग़ज़लें सुनकर ऐसा लगता था मानो कोई अपना इंसान अपनी कहानी सुना रहा हो। यही सादगी उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी।

"लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में,
तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में"

यह शेर केवल एक कविता नहीं, बल्कि समाज की उस त्रासदी का आईना बन गया, जिसे इंसानियत बार-बार झेलती रही है। यही वजह रही कि उनकी शायरी केवल इश्क़ तक सीमित नहीं रही, बल्कि समाज, राजनीति, टूटते रिश्तों और इंसानी संघर्षों की आवाज़ बन गई।

उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के बड़े-बड़े नेता भी समय-समय पर उनके शेरों का इस्तेमाल करते रहे। Narendra Modi ने संसद में विपक्ष पर निशाना साधते हुए उनका मशहूर शेर पढ़ा था—

"जी बहुत चाहता है सच बोलें, क्या करें हौसला नहीं होता।"

वहीं Mallikarjun Kharge ने भी संसद में उनका शेर सुनाकर राजनीतिक संदेश दिया था—

"दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हों।"

Rahul Gandhi, Sushma Swaraj, पूर्व प्रधानमंत्री Indira Gandhi और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति Zulfikar Ali Bhutto तक उनके प्रशंसकों में शामिल रहे।

यह सम्मान किसी साधारण शायर को नहीं मिलता।

उर्दू साहित्य में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें साल 1999 में Padma Shri से सम्मानित किया। इसके अलावा उन्हें Sahitya Akademi पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। लेकिन उनकी असली पहचान पुरस्कारों से नहीं, बल्कि लोगों के दिलों से बनी।

35 लाख+ यूज़र्स और 6 लाख+ सारथियों के साथ 'भारत टैक्सी' बनी दुनिया की सबसे बड़ी मोबिलिटी कोऑपरेटिव

▸▸ भारत टैक्सी से जुड़े ड्राइवरों (सारथियों)की मासिक आय में 25% से 30% तक की वृद्धि, जबकि यात्रियों को मिल रहा है औसतन 15% सस्ता और पारदर्शी किराया

▸▸ 10,000+ सारथियों को सॉफ्ट स्किल्स और डिजिटल हैंडलिंग का मिला प्रोफेशनल प्रशिक्षण

▸▸ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुजरात पुलिस के साथ SOS इंटीग्रेशन

गांधीनगर : जब हम 'सहकारिता' शब्द सुनते हैं, तो अक्सर हमारे जेहन में अमूल की दूध क्रांति का चित्र उभरता है। लेकिन आज गुजरात की सड़कों पर एक नई डिजिटल क्रांति दौड़ रही है जिसका नाम है 'भारत टैक्सी'। यह सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के सपने को सच करते उन हजारों सारथियों की कहानी है, जो अब किसी कंपनी के कर्मचारी नहीं, बल्कि इस मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के खुद मालिक हैं। 5 फरवरी को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई यह पहल, तकनीक और मानवीय गरिमा के संगम का दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुकी है।

भारत टैक्सी के चेयरमैन और अमूल के एमडी जयेन मेहता इस बदलाव को एक बड़ी क्रांति के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार, "भारत टैक्सी ने ड्राइवर-ओन्ड मॉडल को धरातल पर उतारकर यह सुनिश्चित किया है कि राइड की 100% कमाई बिना किसी कटौती के सीधे ड्राइवर्स तक पहुँचे। आज यह दुनिया की सबसे बड़ी मोबिलिटी कोऑपरेटिव के रूप में उभरकर न केवल सारथियों की गरिमा बहाल कर रही है, बल्कि 'सहकार से समृद्धि' के विजन को वैश्विक स्तर पर एक नया बेंचमार्क दे रही है।"

कमीशन का 'खेल' खत्म, अब सारथी ही मालिक

मोबिलिटी सेक्टर में अब तक सारथियों की सबसे बड़ी त्रासदी भारी-भरकम कमीशन और अनिश्चित आय रही है। लेकिन 'भारत टैक्सी' ने इस पुराने ढर्रे को ध्वस्त कर दिया है। यहाँ कोई बिचौलिया या कॉर्पोरेट नहीं है, बल्कि सारथी ही इस कोऑपरेटिव के स्टेकहोल्डर्स हैं। इसका सीधा इम्पैक्ट ग्राउंड जीरो पर दिख रहा है। इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद एक औसत सारथी की मासिक आय में 25% से 30% तक का उछाल आया है। यह आंकड़ा केवल कमाई नहीं, बल्कि उन हजारों परिवारों की खुशहाली का दस्तावेज है जो अब पारंपरिक एग्रीगेटर मॉडल से बाहर निकल रहे हैं।

सारथियों के जीवन में आए इस बदलाव को प्रवीण ठाकोर के अनुभव से बखूबी समझा जा सकता है। वे बताते हैं, "अन्य कंपनियों के साथ काम करना अब फ़ायदेमंद नहीं रह गया था। लेकिन 'भारत टैक्सी' से जुड़ने के बाद हमें बेहतरीन रेट और रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। इस मॉडल से जुड़कर कोई भी सारथी अच्छी कमाई कर अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकता है।"

डायनेमिक प्राइसिंग' से मुक्तिः पारदर्शी सिस्टम से यात्रियों को मिल रही लगभग 15% तक की बचत

भारत टैक्सी केवल सारथियों की आय बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने 'पैसेंजर एक्सपीरियंस' को भी एक नया आयाम दिया है। जहाँ निजी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स में 'डायनेमिक प्राइसिंग' के कारण किराए में अनिश्चितता बनी रहती है, वहीं भारत टैक्सी ने किराया संरचना को स्थिर और पारदर्शी रखा है। इसका सीधा लाभ यात्रियों को मिल रहा है, जिन्हें औसतन 15% तक कम किराया देना पड़ रहा है।

यात्रियों की इस बचत और सारथियों की आज़ादी के इस 'विन-विन' मॉडल की ज़मीनी हकीकत बताते हुए ड्राइवर जनक बारोट कहते हैं, "यहाँ 'जीरो कमीशन' है और भुगतान सीधे हमारे खाते में आता है; हम खुद को इसका मालिक महसूस करते हैं। अन्य कंपनियों के 30/किमी के मुकाबले हम ग्राहकों से 17-18 का किफायती रेट ले रहे हैं, जो उनके लिए भी फायदेमंद है। भविष्य में संस्था के विस्तार के साथ ही हमें पेंशन और बीमा जैसी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा।"

6 लाख+ सारथी और 35 लाख+ यूजर्स का बड़ा नेटवर्क, अब जल्द वडोदरा में भी शुरू होगी भारत टैक्सी

गुजरात में 1 लाख सहित देशभर में 6 लाख से अधिक सारथियों और 35 लाख+ ऐप डाउनलोड्स के साथ 'भारत टैक्सी' तेजी से एक मजबूत राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म बन रही है। अहमदाबाद और सूरत में शानदार सफलता के बाद, अब वडोदरा कंपनी के विस्तार का अगला प्रमुख केंद्र है। अपनी जमीनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए कंपनी 'बिलो द लाइन' (BTL) रणनीति के तहत आईटी पार्क, हाउसिंग सोसायटी और एयरपोर्ट जैसे अधिक आवाजाही वाले क्षेत्रों में सीधे यूजर्स से जुड़कर इसे एक जन-केंद्रित ब्रांड बना रही है।

इस बढ़ते नेटवर्क और आसान प्रक्रिया पर अहमदाबाद रिक्शा चालक एकता यूनियन के प्रेसिडेंट अजय कुमार गुप्ता कहते हैं, "ग्राहकों को यह बात बहुत आकर्षित करती है कि यह 'अपने भारत की कंपनी' है और इसमें सारथियों से कोई कमीशन नहीं लिया जाता। मेरी सभी सारथियों से अपील है कि वे इससे जुड़ें। इसकी प्रक्रिया इतनी आसान है कि ऐप पर खुद दस्तावेज़ सबमिट करने के महज़ 12 घंटों के भीतर अप्रूवल मिल जाता है।"

गुजरात में भारत टैक्सी को मिला राज्य पुलिस का 'सुरक्षा कवच' और इन्टीग्रेटेड ट्रान्ज़िट सिस्टम की सुविधा

सुरक्षा और तकनीक के बेजोड़ तालमेल का प्रमाण गुजरात पुलिस के साथ इसका सीधा SOS इंटीग्रेशन है, जो यात्रियों और सारथियों के लिए एक 'सुरक्षा कवच' की तरह काम करता है। इतना ही नहीं, सोमनाथ और द्वारकाधीश जैसे पावन तीर्थ स्थलों के लिए समर्पित रूट कनेक्टिविटी ने भारत टैक्सी को केवल शहरी परिवहन तक सीमित न रखकर, श्रद्धालुओं की आस्था और भरोसे का सारथी भी बना दिया है।

इतना ही नहीं, सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अब तक 10,000 से अधिक ड्राइवरों को डिजिटल लिटरेसी और सॉफ्ट स्किल्स का गहन प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मेट्रो, GSRTC और एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ इसके 'इन्टीग्रेटेड ट्रान्ज़िट सिस्टम' ने गुजरात में सफर को एक निर्बाध अनुभव में बदल दिया है।

अहमदाबाद मण्डल पर मण्डल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति,की पाँचवी बैठक का आयोजन

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल में दिनांक 28.05.2026 को मण्डल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति (DRUCC) की पाँचवी बैठक मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय, अहमदाबाद में आयोजित की गई। बैठक के प्रारम्भ में मण्डल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने सभी सदस्यों का स्वागत एवं अभिवादन करते हुए उनके-अपने क्षेत्रों से संबंधित सुझाव आमंत्रित किए।

अपने सम्बोधन में मण्डल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने बताया कि नलिया–वायोर के मध्य मालगाड़ी परिवहन सितंबर 2026 तक प्रारंभ करने की योजना है। उन्होंने जानकारी दी कि भारतीय रेल का सबसे बड़ा 98 लाइनों वाला कोचिंग हब वटवा में विकसित किया जाएगा तथा वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो का कार्य भी तीव्र गति से प्रगति पर है। इसके साथ ही सरखेज–धोलेरा सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना के बारे में भी विस्तृत जानकारी साझा की गई।

समिति के सचिव एवं वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक श्री अन्नू त्यागी ने उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए अहमदाबाद मंडल में चल रही विभिन्न गतिविधियों एवं विकासात्मक परियोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से मंडल की प्रमुख उपलब्धियों एवं विकास कार्यों पर प्रकाश डाला।

श्री त्यागी ने बताया कि अहमदाबाद, साबरमती एवं भुज स्टेशनों का मेजर रीडेवलपमेंट कार्य प्रगति पर है, जिनमें साबरमती एवं भुज स्टेशनों का कार्य उन्नत चरण में पहुँच चुका है। इसके अतिरिक्त मंडल के अन्य प्रमुख स्टेशनों का पुनर्विकास "अमृत भारत स्टेशन योजना" के अंतर्गत किया जा रहा है।

अहमदाबाद मंडल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां एवं विकास कार्य

▸▸ अहमदाबाद मंडल पश्चिम रेलवे का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला मंडल है।

▸▸ मंडल द्वारा 412 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस एवं यात्री गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें 118 मूल गाड़ियां शामिल हैं।

▸▸ वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रतिदिन लगभग 1.1 लाख यात्रियों ने अहमदाबाद मंडल से यात्रा प्रारंभ की।

▸▸ मंडल ने पश्चिम रेलवे की कुल यात्री आय में 21% तथा माल लदान में 49% योगदान दिया।

▸▸ भारतीय रेलवे में अहमदाबाद मंडल माल लदान में 8वें तथा माल आय में 7वें स्थान पर रहा।

▸▸ मंडल द्वारा मुंद्रा पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट (कांडला) एवं टूना पोर्ट जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों को रेल कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है।

▸▸ मंडल में 143 यात्री स्टेशन, 33 रेलवे फ्रेट टर्मिनल एवं 7 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल कार्यरत हैं।

▸▸ स्टेशन पुनर्विकास एवं अमृत भारत स्टेशन योजना

▸▸ अहमदाबाद स्टेशन का 2379 करोड़ की लागत से विश्वस्तरीय पुनर्विकास कार्य तेजी से प्रगति पर है।

▸▸ साबरमती बीजी एवं साबरमती जंक्शन स्टेशन पुनर्विकास कार्य लगभग 73% तक पूर्ण हो चुका है।

▸▸ न्यू भुज स्टेशन पुनर्विकास कार्य 76% तक पूर्ण हो चुका है।

▸▸ अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत मंडल के 16 स्टेशनों का विकास 515.03 करोड़ की लागत से किया जा रहा है।

▸▸ सामाखियाली स्टेशन के कार्य पूर्ण हो चुके हैं जबकि कालोल, हिम्मतनगर, भचाऊ आदि स्टेशनों पर तेजी से कार्य जारी है।

नई ट्रेन सेवाएं एवं विशेष गाड़ियां

▸▸ ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान यात्रियों की सुविधा हेतु कई विशेष ट्रेनों का संचालन किया गया।

▸▸ भुज–दिल्ली एक्सप्रेस का नई ट्रेन सेवा का संचालन 22 मई 2026 को प्रारंभ हुआ है।

▸▸ उदयपुर सिटी–असारवा वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ 16 फरवरी 2026 को किया गया।

गौरवपूर्ण उपलब्धियां एवं माल व्यवसाय

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में खेड़ब्रह्मा–हिम्मतनगर सेक्शन राष्ट्र को समर्पित किया गया।

▸▸ मंडल ने स्टेनलेस स्टील कंटेनरों द्वारा औद्योगिक नमक लदान की अभिनव शुरुआत की।

▸▸ बेचराजी से ACT-1 ऑटोमोबाइल रेक लोड कर 264 वाहनों का परिवहन किया गया।

▸▸ उंझा से मिर्जा (असम) तक मसालों की पहली पार्सल रेक चलाई गई।

▸▸ लिन्च से जम्मू-कश्मीर तक दुग्ध उत्पादों की पहली कार्गो रेक भेजी गई।

▸▸ बैठक के दौरान समिति के सदस्यों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित रेल समस्याओं, ट्रेनों के ठहराव, ट्रेनों का विस्तार, ट्रेनों का स्टोपेज प्रदान करने, नई ट्रेन सेवा शुरू करने एवं अंडर ब्रिज और रोड ओवर ब्रिज बनाने तथा नई परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन तथा स्टेशनों पर बेहतर यात्री सुविधाएँ उपलब्ध कराने स्टेशन पर ठंडे पानी की समुचित व्यवस्था, साफ-सफाई जैसे महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए।

इस अवसर पर समिति के सदस्य एवं अपर मण्डल रेल प्रबंधक श्रीमती मंजू मीणा और मण्डल के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे तथा बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया।

पांच साल बाद, राजुभाई ठक्कर ने अदालत के आदेश से अपनी सलाबतपुरा संपत्ति पर पुनः कब्जा प्राप्त कर लिया

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत

सूरत शहर में दुर्घटना निवारण केंद्र के प्रमुख राजुभाई सी. ठक्कर, जो सूरत जिला नगर, सलाबतपुरा, बालाभाई स्ट्रीट, वार्ड नंबर 3, नोट नंबर 2241 में अपना व्यवसाय चलाते हैं, सेठ बालाभाई गोपालभाई धार्मिक एवं धर्मार्थ ट्रस्ट, सत्यनारायण मंदिर की संपत्ति का प्रबंधन कर रहे हैं। उक्त संपत्ति का पिछला हिस्सा पिपर्डी स्ट्रीट पर स्थित है, जहां वे एयरलाइट कॉर्पोरेशन और एयरलाइट डेकोरेशन के नाम से खिड़की के पर्दे बनाने और बेचने का व्यवसाय करते थे। मई 2021 में, सत्यनारायण मंदिर के प्रबंध न्यासी, संदीप गिरीशचंद्र पटेल ने पुलिस की मिलीभगत से उक्त स्थान पर चोरी और लूटपाट की और अवैध रूप से कब्जा कर लिया। इस संबंध में, राजुभाई सी. ठक्कर ने 25/05/2021 को सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इसके 10 दिन बाद तत्कालीन निजी जांच अधिकारी एम.वी. किकानी और पुलिस जांच अधिकारी ने... एस.जी. चौहान ने राजूभाई सी. ठक्कर के खिलाफ झूठी एफआईआर में चोर को शिकायतकर्ता और शिकायतकर्ता को आरोपी बना दिया। इस मामले में मेरी शिकायत वर्तमान में अदालत में लंबित है। इस मामले में हेल्पलाइन 14449 पर पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसकी जांच पुलिस आयुक्त कार्यालय के इको सेल में चल रही है। इसके अलावा, राजूभाई सी. ठक्कर ने केस संख्या 1/2021 में कब्जे के संबंध में शिकायत दर्ज कराई और स्वयं वकील के रूप में मुकदमा लड़ा। तत्कालीन कतरगाम मामलातदार हुड साहब ने 8 जनवरी 2024 को राजूभाई सी. ठक्कर के पक्ष में फैसला सुनाया। समावाला सत्यनारायण मंदिर के ट्रस्टी संदीप गिरीशचंद्र पटेल ने केस संख्या 10/2024 से जिला न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की। इस पुनरीक्षण याचिका में भी राजूभाई ठक्कर ने स्वयं वकील के रूप में पैरवी की। जिला न्यायालय के 12वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री अमितकुमार नरेंद्रभाई दवे साहब ने 1/10/2024 को समावाला ट्रस्टियों की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। इसके बाद समावाला ने फिर से उच्च न्यायालय का रुख किया। राजुभाई सी. भी पक्षकार (वकील) के रूप में उच्च न्यायालय में उपस्थित हुए और उन्होंने क्रॉसिंग पर साक्षात्कार दिया। चूंकि ठक्कर अब उपस्थित नहीं थे, इसलिए वादी ने 12/02/2026 को श्री आर. मेंगड़े साहब की अदालत से उच्च न्यायालय में अपनी याचिका वापस ले ली। उपरोक्त मामले के बाद, 16/05/2026 को कतरगाम मामलतदारश्री ने राजुभाई ठक्कर को कब्जा सौंपने का आदेश दिया। इसके कार्यान्वयन के लिए सूरत के अतिरिक्त कलेक्टर श्री और मजिस्ट्रेट साहब श्री रबारी साहब ने इसे अपने समक्ष प्रस्तुत किया। 21/05/2026 को, कतरगाम मामलतदार दिनेशभाई गामित के मार्गदर्शन में, कतरगाम सर्कल ऑफिसर श्री क्रुणालभाई पटेल नाओ सलाबतपुरा सत्यनारायण मंदिर स्थल पर, निजी जांच अधिकारी श्री आर. ए. जडेजा साहब के मार्गदर्शन में, पुलिस काफिले और पुलिस व्यवस्था के साथ, उक्त स्थान का कब्जा राजुभाई सी. ठक्कर को सौंप दिया गया। इस प्रकार सत्य की विजय हुई और राजुभाई ठक्कर ने पांच साल पुराने सदरहु मामले में सफलता प्राप्त की।

सूरत का नया सिविल अस्पताल: सुविधाओं की कमी और गरीब मरीजों की समस्याओं पर समीक्षा

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

सूरत का नया सिविल अस्पताल दक्षिण गुजरात का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है। महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों से भी मरीज इलाज के लिए यहां आते हैं। सूरत शहर में देशभर के लोग रहते हैं। इसी वजह से अगर उन्हें या उनके रिश्तेदारों को इलाज की जरूरत पड़ती है, तो वे सूरत के इस अस्पताल से संपर्क करते हैं। सिविल अस्पताल में कई तरह के ऑपरेशन होते हैं। लेकिन इतने सालों से मौजूद होने के बावजूद सरकार यहां हृदय रोग, गुर्दे, यकृत और मस्तिष्क रोगों का इलाज उपलब्ध कराने में नाकाम रही है। गुर्दा अस्पताल की इमारत करोड़ों रुपये की लागत से बनी है, लेकिन कर्मचारियों और उपकरणों की कमी के कारण यह धूल फांक रही है। और अस्पताल आने वाले मरीजों को हृदय, गुर्दे, यकृत और मस्तिष्क के इलाज के लिए अहमदाबाद या मुंबई तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। आर्थिक रूप से सक्षम मरीज निजी अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं। वहीं गरीब परिवारों के मरीज मौत के मुंह में धकेले जा रहे हैं। अगर सूरत के सिविल अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में हृदय रोग, गुर्दे, यकृत और मस्तिष्क रोगों का इलाज उपलब्ध कराया जाए, तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र भी इसका लाभ उठा सकेंगे। सूरत के सिविल अस्पताल और मेडिकल कॉलेज को इस दिशा में सोचना चाहिए। सूरत शहर के तीन सांसदों और लगभग 12 विधायकों को सिविल अस्पताल को इस तरह का उच्च स्तरीय उपचार प्रदान करने के बारे में सोचना चाहिए। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है कि नए सिविल अस्पताल में सुविधाओं के नाम पर गरीब मरीजों को तकलीफ झेलनी पड़े, जबकि गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री सूरत से ही हों? इस नए सिविल अस्पताल में गरीब मरीजों के लिए बाईपास सर्जरी के उपकरणों की कमी, आधुनिक मशीनों का अभाव और डॉक्टरों की भी कमी के कारण, जाति-धर्म के भेदभाव के बिना, आदिवासी और दलित समेत गरीब मरीज इतनी दूर से आते हैं और उन्हें इलाज के लिए दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ती हैं? सरकार दवाइयों और उपकरणों के लिए करोड़ों रुपये का अनुदान देती है, फिर भी मरीजों को अच्छी हालत में स्ट्रेचर या व्हीलचेयर नहीं मिलतीं। शर्म की बात है

कि मरीजों को वार्ड तक ले जाने के लिए उनके रिश्तेदारों को खुद स्ट्रेचर खींचकर ले जाना पड़ता है। मरीजों को दिए जाने वाले गद्दे और चादरें भी बदबूदार होती हैं। यहां तक कि मरीजों के खाने के बर्तन भी अलमारियों में रखे रहते हैं। संक्षेप में कहें तो, अस्पताल के प्रशासन के लिए अच्छे अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी है। अगर स्वास्थ्य मंत्री साल में सिर्फ एक बार ऐसे अधिकारी का तबादला कर दें, तो प्रशासन में सुधार नहीं होगा।

एक तरफ जहां ठेकेदार अपने चहेतों को नए भवन निर्माण के ठेके देकर अपनी जेबें भर रहे हैं, वहीं भविष्य में बनने वाले उन भवनों का क्या उपयोग है जो डॉक्टरों और मशीनरी की कमी के कारण खंडहर में बदल जाते हैं और भ्रष्टाचार के प्रतीक बन जाते हैं?

अहमदाबाद मंडल पर व्यापक पर्यावरण जागरूकता अभियान,अहमदाबाद मंडल का महा-अभियानः 'विश्व पर्यावरण दिवस 2026' पर हरित और सतत रेल की ओर कदम

भारतीय रेलवे द्वारा "विश्व पर्यावरण दिवस 2026" के उपलक्ष्य में 15 मई 2026 से 5 जून 2026 तक देशव्यापी व्यापक पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में, पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल द्वारा पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और सतत जीवनशैली (Sustainable Lifestyle) को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न रेलवे स्टेशनों, रेलवे कॉलोनियों तथा रेलवे स्वास्थ्य इकाइयों में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रम एवं जनजागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं।

इस तीन सप्ताह लंबे अभियान को मंडल द्वारा अलग-अलग चरणों में विभाजित कर बेहद योजनाबद्ध और प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित हैः

हरित रेल परिचालन और "एक पेड़ माँ के नाम"

वर्तमान में चल रहे इस चरण में पर्यावरण को नया जीवन देने के लिए हरित आवरण (Green Cover) बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा हैः

वृहद वृक्षारोपणः माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मंडल भर में "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के अंतर्गत बड़े पैमाने पर सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रेलवे कॉलोनियों, स्टेशनों के सर्कुलेटिंग एरिया और खाली भूखंडों को हरा-भरा बनाने और पार्कों के सुंदरीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

सतत जीवनशैली गतिविधियाँः ई-वेस्ट (E-Waste) प्रबंधन, कचरे के पुनर्चक्रण (Recycling) तथा पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली के तहत शारीरिक फिटनेस और आउटडोर एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जा रहा है।

OSOP का सहयोगः 'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट' (OSOP) योजना के तहत स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए जा रहे कपड़े और जूट के थैलों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि प्लास्टिक बैग का विकल्प मिल सके।

प्रतियोगिताएं एवं निरीक्षणः रेल कर्मचारियों के बच्चों और यात्रियों के लिए पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विषय पर चित्रकला, निबंध लेखन एवं प्रश्नोत्तरी (Quiz) प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इसके साथ ही, स्टेशनों पर ट्रेनों के बायो-टॉयलेट और अपशिष्ट निपटान प्रणालियों का अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किया जा रहा है।

अभियान का शुभारंभ एवं डिजिटल जागरूकता

अभियान के प्रथम चरण में संपूर्ण अहमदाबाद मंडल में औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके तहत डिजिटल इंडिया और पेपरलेस प्रणाली को बढ़ावा देते हुए बड़े पैमाने पर काम किया गयाः

डिजिटल आउटरीचः सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर #MissionLiFE और WED 2026 थीम के तहत सघन अभियान चलाया गया।

यात्री संवेदीकरणः रेलवे स्टेशनों और कार्यालय परिसरों में जलवायु परिवर्तन, "सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ना कहें" तथा पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली से जुड़े आकर्षक पोस्टर, बैनर और डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड प्रदर्शित किए गए।

पेपरलेस यात्रा को बढ़ावाः यात्रियों को RailOne और अन्य ऑनलाइन ऐप के माध्यम से डिजिटल टिकटिंग अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया गया ताकि कागज की बचत की जा सके।

कार्यशालाएं एवं क्षमता निर्माणः रेलवे कर्मचारियों के लिए जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट प्रबंधन (Waste Management) और पर्यावरण-अनुकूल कार्यप्रणाली पर विशेष कार्यशालाएं आयोजित की गईं। साथ ही यात्रियों को "अपनी पानी की बोतल साथ रखें" संदेश के तहत पुनः उपयोग योग्य बोतलों और कंटेनरों का उपयोग करने की शपथ दिलाई गई।

स्वच्छता, कचरा प्रबंधन एवं ऊर्जा संरक्षण के कड़े कदम

इस चरण के दौरान कचरे के उचित निपटान और ऊर्जा की भारी बचत के लिए अनुकरणीय कदम उठाए गए:

कचरा पृथक्करण (Waste Segregation): प्लेटफॉर्मों पर गीला और सूखा कचरा अलग-अलग करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। स्थानीय समुदायों और स्वयंसेवी संस्थाओं (NGOs) के समन्वय से स्टेशनों के आसपास स्वच्छता अभियान चलाए गए।

इको-फ्रेंडली कैटरिंगः IRCTC के सहयोग से वेंडिंग स्टॉलों और ट्रेनों में जैव-अवक्रमणीय (Biodegradable) एवं प्लास्टिक-मुक्त कटलरी के उपयोग को अनिवार्य रूप से बढ़ावा दिया गया।

ऊर्जा संरक्षण की मिसाल (Energy Conservation): मंडल रेल प्रबंधक (DRM), अहमदाबाद के कुशल दिशा-निर्देशानुसार ऊर्जा संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए 19 मई 2026 को मंडल कार्यालय अहमदाबाद में सभी एयर कंडीशनर (AC) और लाइटें एक घंटे के लिए बंद रखी गईं। इसी प्रकार, 20 मई 2026 को प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक मंडल की सभी रेलवे कॉलोनियों में लाइटें बंद रखकर समाज को बिजली बचाने का एक बड़ा संदेश दिया गया।

प्लास्टिक उन्मूलन, रिसाइक्लिंग एवं नुक्कड़ नाटक

प्लास्टिक प्रदूषण को जड़ से खत्म करने के लिए अहमदाबाद मंडल द्वारा ज़मीनी स्तर पर कड़े प्रयास किए गए:

सख्त निगरानीः स्टेशनों पर लगी प्लास्टिक बोतल क्रशिंग मशीनों (PBCM) के सुचारू संचालन की समीक्षा की गई। स्टेशन वेंडर स्टॉलों पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक (SUP) के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए विशेष फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा निगरानी रखी गई।

माइक्रोप्लास्टिक नियंत्रणः विक्रेताओं और पैंट्री कर्मचारियों को दूध, छाछ या अन्य खाद्य पदार्थों के पैकेजिंग बैग को पूरी तरह से अलग न काटते हुए, आंशिक रूप से काटने (Partial Cutting) के लिए शिक्षित किया गया, ताकि कचरे के छोटे टुकड़े पर्यावरण में मिलकर माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण न फैलाएं।

सांस्कृतिक माध्यम से अलखः यात्रियों को जागरूक करने के लिए असारवा स्टेशन और ईएलएफ (ELF) वटवा में स्थानीय कलाकारों द्वारा पर्यावरण केंद्रित नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया गया, जिसे यात्रियों की भारी सराहना मिली। साथ ही जल पुनर्भरण (Water Recharging) केंद्रों का सघन निरीक्षण भी किया गया।

"भारतीय रेलवे द्वारा चलाया जा रहा यह 21 दिवसीय अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा की बचत और सतत विकास के प्रति जनसामान्य को जोड़ने का एक पावन जन-आंदोलन है। अहमदाबाद मंडल भविष्य में भी पर्यावरण के अनुकूल, कार्बन-न्यूट्रल और हरित रेल परिचालन के लिए पूरी तरह प्रतिज्ञाबद्ध है।" भारतीय रेलवे द्वारा यह अभियान पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, ऊर्जा संरक्षण एवं सतत विकास के प्रति जनसामान्य में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

गोधरा में यार्ड इम्प्रूवमेंट का महत्पूर्ण इंफ्रा वर्क पूर्ण

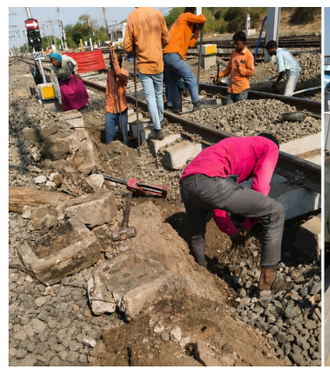

रेलवे अधोसंरचना को अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से वडोदरा मंडल के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा गोधरा यार्ड में दिनांक 25 मई, 2026 को व्यापक यार्ड इम्प्रूवमेंट एवं ड्रेनेज सुधार कार्य किए गए। इन कार्यों से परिचालन में संरक्षा, ट्रैक स्थिरता तथा रेल परिचालन की समग्र विश्वसनीयता में वृद्धि के साथ साथ गोधरा यार्ड में जल निकासी व्यवस्था में भी उल्लेखनीय सुधार होगा।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गोधरा यार्ड में डाउन मेन लाइन पर ब्लॉक लेकर इस कार्य के अंतर्गत पॉइंट संख्या 121, 115, 109 एवं 106 पर व्यापक अनुरक्षण एवं नवीनीकरण कार्य किए गए, जिनमें कुल 350 पी एंड सी स्लीपरों का नवीनीकरण किया गया। साथ ही एमके-V ERC, लाइनर एवं रबर पैड के साथ सम्पूर्ण फिटिंग नवीनीकरण कार्य किया गया तथा सभी पॉइंट्स पर स्लीपर स्पेसिंग एवं स्लीपर स्क्वेरिंग कार्य भी सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

इंफ्रा के इस महत्पूर्ण कार्य में पुराने साधारण स्लीपरों के स्थान पर 391 वाइड बेस स्लीपरों से नवीनीकरण किया गया। 78 स्लीपरों का डीप स्क्रीनिंग कार्य के साथ नवीनीकरण किया गया, जिसमें 350 मिमी बैलास्ट कुशन सुनिश्चित किया गया।वाइड बेस स्लीपर सेक्शन में TSR कार्य के साथ सम्पूर्ण फिटिंग नवीनीकरण भी किया गया।

गोधरा यार्ड क्षेत्र में इन सुधार कार्यों से ट्रैक संरक्षा, रेल परिचालन की विश्वसनीयता, राइडिंग गुणवत्ता तथा जल निकासी व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार होगा।